

मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी : पीएम मोदी

मणिपुर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर के इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें मंत्रीपुखरी स्थित सिविल सचिवालय, मंत्रीपुखरी में IT SEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और चार जिलों में महिलाओं के लिए अनूठा इमा मार्केट शामिल हैं।

21वीं सदी का ये समय 'नॉर्थ ईस्ट' का है

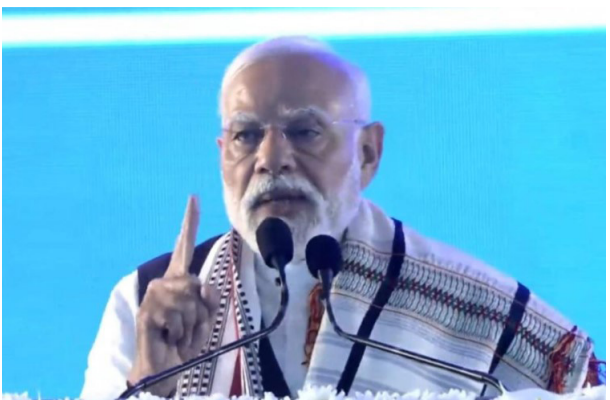
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, "आजादी के बाद देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहां सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले। अब 21वीं सदी का ये समय 'ईस्ट' का है, 'नॉर्थ ईस्ट' का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है।"

मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत

मणिपुर के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है।

मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है और मिलकर जाना है। भारत की आजादी की



लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है। यह मणिपुर की ही धरती थी जहां भारतीय राष्ट्रीय सेना ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने एक ओर बड़ा कदम उठाया है। अंडमान और निकोबार महाद्वीप में माउंट हैरिघट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है।

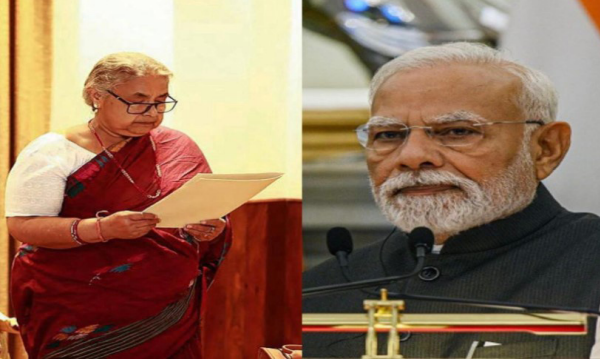
विकास प्रोजेक्ट्स के लिए मणिपुर के लोगों को दी बधाई

पीएम मोदी ने कहा, "आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों-करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। यह परियोजनाएं आप सभी लोगों का जीवन आसान बनाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे-बेटियों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे। मैं मणिपुर के लोगों को सभी विकास योजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।"

पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से कहा

वहीं, नेपाल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल, भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं। आस्था से जुड़े हैं। साथ मिलकर

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की को दी शुभकामनाएं

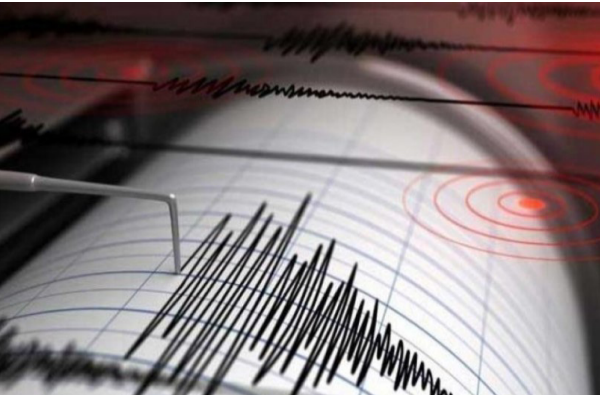


नेपाल (एजेंसी)। नेपाल में 'जेन-जी' विरोध के कारण हुए तख्तापलट के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्होंने शुक्रवार शाम को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, "नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

अंप्रेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अंप्रेशन सिंदूर का जिक्र किया, उन्होंने कहा, "आज भी मणिपुर की अनेक संतानें देश के अलग-अलग हिस्सों में मां भारती की रक्षा में जुटी हैं अभी अंप्रेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा है। हमारे सैनिकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राहि-त्राहि करने लगी। भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे-बेटियों का शौर्य शामिल है। ऐसे ही हमारे जांबाज, शहीद दीपक चिंगामखम के शौर्य को मैं आज नमन करता हूँ। अंप्रेशन सिंदूर के दौरान उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा।"

रूस के कामचटका में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी



रूस (एजेंसी)। रूस के कामचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास शनिवार को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएससीएस) के अनुसार, भूकंप रूसी शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किलोमीटर (69 मील) पूर्व में कामचटका क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र में, 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया।

भूकंप के बाद, कामचटका क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की। कामचटका क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि समुद्र तट और सुनामी के खतरे वाले अन्य क्षेत्रों में जाते समय विशेष रूप से सावधान रहें। गवर्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने और आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी।

इस बीच, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से जापानी मीडिया आउटलेट एनएचके वर्ल्ड ने बताया कि कामचटका में भूकंप से जापान के तट पर मामूली ज्वारीय उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन देश में भूकंप से नुकसान का कोई खतरा नहीं है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती के अनुसार, यह भूकंप 30 जुलाई को कामचटका में आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली

एमपी के सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, बाल-बाल बचे

मध्यप्रदेश (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट दौरा शनिवार को उस समय चर्चा में आ गया, जब उनका हॉट एयर बैलून हवा में नहीं उड़ पाया। तेज हवा और अचानक बढ़ी आग की लपटों के चलते सुरक्षा कारणों से बैलून की उड़ान रोक दी गई। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और मुख्यमंत्री सुरक्षित रहे।

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार शाम मंदसौर जिले के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ किया। रात उन्होंने गांधीसागर के हिंगलाज रिसॉर्ट में नाइट हाउट किया। शनिवार सुबह सीएम ने चंबल नदी में बोटिंग का आनंद लिया और इसके बाद हॉट एयर बैलून की सवारी के लिए पहुंचे।

सीएम मोहन यादव जैसे ही हॉट एयर बैलून में सवार हुए, तेज हवा चलने लगी। इस कारण बैलून उड़ान नहीं भर पाया। इसी बीच बैलून के निचले हिस्से में आग की



लपटें तेज हो गईं। सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते ट्रॉली संभाली और मुख्यमंत्री को समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग बुझाई। वहीं, सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को जिस ट्रॉली में बैठाया गया था, उसे मजबूती से पकड़े रखा और उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया। मुख्यमंत्री यादव बैलून की सवारी नहीं कर पाए। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से इंदौर रवाना हो गए। इससे पहले शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने मंदसौर जिले के गांधीसागर में चंबल नदी की अदृष्ट

नेपाल के 'जेन-जी' आंदोलन से प्रभावित हुआ उत्तराखंड का बनबसा बाजार, 90 फीसद व्यापार ठप

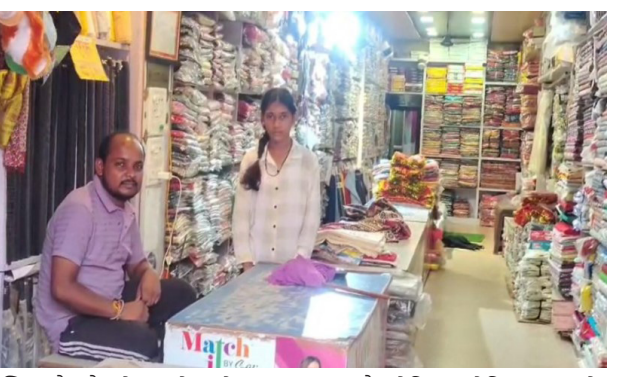
नेपाल (एजेंसी)। नेपाल में जेन-जी आंदोलन के बाद पैदा हुई अशांति ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित उत्तराखंड के बनबसा बाजार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बीते तीन दिनों से सीमा पर सत्राटा छा गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों का 90 प्रतिशत से अधिक कारोबार ठप हो चुका है।

बनबसा बाजार, जो मुख्य रूप से नेपाली ग्राहकों पर निर्भर है, अब पूरी तरह शांत हो गया है। व्यापारियों को प्रतिदिन 40 से 50 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हो रहा है। नेपाली शहर महेंद्रनगर (कंचनपुर) में लगे कर्फू के कारण सीमा पर आवागमन पूरी तरह बंद है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। स्थानीय व्यापारी अब नेपाल में शांति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनका कारोबार पटरी पर लौट सके।

नेपाल में सितंबर में शुरू हुए जेन-जी आंदोलन ने देश को हिला दिया। यह आंदोलन शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ था, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म (नेपो किड्स की विलासिता) और आर्थिक असमानता के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों में बदल गया। युवा पीढ़ी (13 से 28 वर्ष के बीच) ने काठमांडू और अन्य शहरों में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो नेपाल की पहली महिला पीएम हैं। नेपाल आर्मी ने सुरक्षा संभाली है और कर्फू में सुबह-शाम छूट दी जा रही है। हालांकि, स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है।

इस अशांति का असर भारत-नेपाल सीमा पर साफ दिख रहा है। बनबसा बाजार चंपावत जिले में स्थित है और नेपाल के महेंद्रनगर से सटा हुआ है। यह बाजार दैनिक आवश्यकताओं जैसे नमक, तेल, चीनी, मसाले, परचून, सब्जी, गुड़ आदि के लिए नेपाली ग्राहकों का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा, कपड़े, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, दवाइयां और अन्य महत्वपूर्ण सामान भी यहां से नेपाल निर्यात होते हैं। सामान्य दिनों में बाजार नेपाल के हजारों ग्राहकों से गुलजार रहता है, लेकिन अब नेपाली ग्राहक न आने से 90-95 प्रतिशत दुकानें बंद पड़ी हैं। केवल 10 प्रतिशत स्थानीय भारतीय ग्राहकों पर निर्भरता बची है। व्यापारी दिनों में ही दुकानों पर खाली बैठे हैं या गहियों पर सो रहे हैं। मीना बाजार पूरी तरह धराशाही हो चुका है, जहां कई दुकानदार शाम 4 बजे ही घर लौट जाते हैं।

स्थानीय व्यापार मंडल के अनुसार, बनबसा का कारोबार पूरी तरह नेपाल पर आश्रित है। सामान्यतः दैनिक व्यापार 60-70 लाख रुपये तक होता था, जो अब घटकर मात्र 1-2 लाख रह गया है। इससे आर्थिक संकट गहरा गया है। व्यापारियों की चिंता दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों को लेकर है। नेपाल में दशहरा सबसे बड़ा त्योहार है, जब बनबसा बाजार में प्रतिदिन 2.5 से 3 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। यदि स्थिति यूं ही बनी रहती, तो त्योहारों पर भी असर पड़ेगा और व्यापारियों की जीविका खतरे में पड़ जाएगी। 1960 से यहां व्यापार चला आ



रहा है, लेकिन कोविड काल के बाद यह पहली बार इतना बुरा दौर आया है। नेपाली व्यापारियों के साथ लूटमार की घटनाओं से उनका कारोबार भी प्रभावित हुआ है, जिसका खामियाजा भारतीय पक्ष को भुगतान पड़ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत भंडारी ने कहा, "नेपाल में स्थिति विषम है। हम 1960 से यहां व्यापार कर रहे हैं। यहां का 90 प्रतिशत कारोबार नेपाल पर निर्भर है। आंदोलन के कारण सब ठप हो गया। नेपाल और हमारा व्यापार आपस में जुड़ा है। वहां लूटमार से नेपाली व्यापारी पीछे हट गए। हमने कोविड जैसी चुनौतियां देखी हैं, लेकिन यह तनाव भरा है। दशहरा-दीपावली पर बिक्री होती है, यदि यूं ही चला तो सब शून्य हो जाएगा। हमारी जीविका यही है।"

महामंत्री अभिषेक गोयल ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया, "बनबसा का व्यापार नेपाल पर आश्रित है। बांडर क्षेत्र के बाजार सीमा पर निर्भर रहते हैं। दैनिक 60-70 लाख का व्यापार अब 1-2 लाख पर सिमट गया। आर्थिक नुकसान हो रहा है। उम्मीद है जल्द हालात सामान्य हों, ताकि रोटी-बेटी का संबंध फिर मजबूत हो।" व्यापारी पंकज कुमार अप्रवाल ने कहा, "हालात बहुत खराब है। दुकान में एक ग्राहक भी नहीं। हमारा व्यापार नेपाल पर निर्भर है। वहां की स्थिति का असर यहां पड़ रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द सामान्य हो, ताकि व्यापार तेज हो।"

योगी, नाथ एवं सिद्ध समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भजनलाल शर्मा से की भेंट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर योगी, नाथ एवं सिद्ध समाज के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान एवं विकास के लिए किए गए निर्णयों, संचालित की जा रही योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सांसद मदन राठौड़ उपस्थित रहे।



कोलकाता में भारी सुरक्षा के बीच 'द बंगाल फाइल्स' का पहला शो, गृह मंत्री ने ली व्यक्तिगत रुचि



नई दिल्ली (एजेंसी)। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी परिसर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन सभागार में शनिवार शाम द बंगाल फाइल्स का पहला विशेष शो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित किया गया। यह शो सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन 'खोला हावा' की ओर से रखा गया था, जिसमें फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री और अभिनेत्री-निर्माता पल्लवी जोशी भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार ने विशेष सतर्कता बरती। शुक्रवार से ही नेशनल लाइब्रेरी में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई थी। बताया जाता है कि इस स्क्रीनिंग को संभव बनाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं हस्तक्षेप किया और पूरे मामले में व्यक्तिगत रुचि दिखाई।

'खोला हावा' के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्वसांसद स्वप्न दासगुप्ता ने कहा, "इतिहास दिखाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्री ने इस मामले में सीधी मदद की, जिसके चलते यह शो संभव हो सका। यह एक प्राइवेट, इन्वाइट-ओनली स्क्रीनिंग है, इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं है। फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है और यदि कोई बाधा डाली जाती है, तो यह केवल राजनीतिक कारणों से होगा।"

फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा, "यह कोलकाता में पहला शो है, और उम्मीद है कि आगे भी कई जगह ऐसे शो होंगे।" वहीं, अभिनेत्री और निर्माता पल्लवी जोशी भावुक नज़र आईं। उन्होंने कहा "बंगाल में बनी फिल्म को बंगाल में ही दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह इतनी भारी सुरक्षा में स्क्रीनिंग करनी पड़ी, उसे देखकर मन दुखी हो गया, क्या इतिहास को दिखाना भी गुनाह है?"

'द ताशकंद फाइल्स' और 'द कश्मीर फाइल्स' चर्चा में रही थीं। फिल्म 1946 में कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हुए दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल में शुरू से ही विवाद बना रहा। पहले एक प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैन ने ट्रेलर लॉन्चकैसिल कर दिया, फिर होटल में किए गए कार्यक्रम को पुलिस हस्तक्षेप से बीच में रोकना पड़ा।

निर्माताओं का आरोप है कि राजनीतिक दबाव और डर के कारण राज्य में फिल्म पर एक तरह का "अनौपचारिक प्रतिबंध" लगाया गया। इसके बावजूद कोलकाता में इस स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन भाजपा समर्थित संगठन 'खोला हावा' ने कराया। आयोजन समिति का कहना है कि अगर यह सफल रहा तो आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे प्राइवेट शो आयोजित किए जाएंगे।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय...

प्रिंट व सोशल मीडिया को एक ही तराजू पर न तोलें

सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसने संवाद और सूचना का दायरा सीमाओं से परे कर दिया है। कोई भी व्यक्ति कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक आंदोलनों को गति देने और लोकतंत्र को मजबूत करने में सोशल मीडिया की भूमिका अहम है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, यही सोशल मीडिया आज फेक न्यूज़, अफवाह और दुष्प्रचार का गढ़ भी बन गया है। सोशल मीडिया को केवल संवाद और सूचना का जरिया मान लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस पर फैलाई जा रही खबरें कई बार समाज को गुमराह कर देती हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों की ताजा घटनाएं इसका उदाहरण हैं, जहां सोशल मीडिया के जरिए फैले दुष्प्रचार ने राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक टकराव को जन्म दिया। यह स्थिति बताती है कि यदि सोशल मीडिया को बिना नियंत्रण और जिम्मेदारी के छोड़ा गया तो यह लोकतंत्र और समाज, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सोशल मीडिया पर कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी फर्जी, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के आने से यह काम और भी कठिन हो गया है। अब न केवल फर्जी खबरें गढ़ी जा रही हैं, बल्कि फोटो और वीडियो भी इतने चालाकी से बदले जाते हैं कि आम आदमी को असल और नकली में

फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि लोग अनजाने में इन खबरों को सच मानकर आगे बढ़ा देते हैं और धीरे-धीरे यह अफवाह एक बड़े झूठ का रूप ले लेती है। प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया की तुलना करना इसलिए भी सही नहीं है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में खबरों को प्रकाशित होने से पहले एक जिम्मेदारी और जवाबदेही की प्रक्रिया से गुजरना होता है। अखबार और पत्रिकाओं में संपादकीय छानबीन, तथ्यों की पुष्टि और संपादकीय मानदंड मौजूद रहते हैं। इस कारण प्रिंट मीडिया अपेक्षाकृत विश्वसनीय माना जाता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी जांच-पड़ताल के अपनी बात साझा कर सकता है। यहां खबरें 'वायरल' होने की होड़ में अक्सर तथ्यों से परे निकल जाती हैं। यदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल सही सूचनाओं और जन-जागरूकता के लिए हो तो यह समाज के लिए अमूल्य समान है। किसान आंदोलन, प्राकृतिक आपदाओं में मदद और शिक्षा-संवाद जैसे क्षेत्रों में सोशल मीडिया ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। लेकिन जब वही सोशल मीडिया राजनीतिक स्वार्थों, अंतरराष्ट्रीय साजिशों या व्यक्तिगत फायदे का साधन बन जाता है, तब यह समाज के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया को एक जिम्मेदारी के साथ लेने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। केवल तकनीक और कानून से ही नहीं, बल्कि समाज को भी जागरूक होकर अपनी भूमिका निभानी होगी।

टैरिफ वॉर: भारत की रणनीति और ट्रंप का दोहरा रवैया

-ट्रंप का दोहरा रवैया: दोस्ती के दावे, दबाव की हकीकत

आज की दुनिया में आर्थिक ताकत किसी भी देश की विदेश नीति, वैश्विक पहचान और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। आर्थिक टकराव अक्सर व्यापार युद्ध या टैरिफ वॉर के रूप में सामने आता है। हाल के वर्षों में अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ विवाद ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भारत के लिए दोस्ताना भी रहा और दबावपूर्ण भी। यह दोहरा रवैया भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया। भारत को इस दौर में एक संतुलित, बहुपक्षीय और दीर्घकालिक रणनीति अपनानी पड़ी। अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच भारत ने रूस, चीन, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका एक 'बैलेंसर' की तरह सामने आई—न तो अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ना और न ही अपनी आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रखना।

टैरिफ वॉर की पृष्ठभूमि
टैरिफ वॉर का अर्थ है कि एक देश पर अपने व्यापारिक साझेदार देशों पर ऊंचे कर (ड्यूटी/टैरिफ) लगाता है ताकि उनके उत्पाद उसकी घरेलू मंडी में महंगे हो जाएं और अपने देश की कंपनियों को लाभ मिले। ट्रंप प्रशासन ने "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत चीन, यूरोप, मेक्सिको और भारत सहित कई देशों पर ऊंचे टैरिफ लगाए। भारत, जो अमेरिकी बाज़ार में आईटी सेवाओं से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम और दवाइयों का बड़ा सप्लायर है, सीधे इस नीति की चपेट में आया। साथ ही, रूस से भारत का तेल व्यापार और रक्षा सौदे भी अमेरिका को खटकने लगे।

भारत पर अमेरिकी टैरिफ का असर
अमेरिका ने भारत पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाए, उनके प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में दिखे: स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर - भारतीय निर्यात महंगे हो गए,

जिससे अमेरिकी खरीदारों ने आयात घटाया। कृषि उत्पाद - भारत के मसाले, चाय-कॉफी और कुछ कृषि वस्तुओं पर भी असर पड़ा। फार्मा सेक्टर - हालांकि भारतीय दवाइयों अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए अभी भी सस्ती रहीं, लेकिन नियामक दबाव बढ़ गया। आईटी सेवाएँ - वीज़ा पॉलिसी और शुल्क बढ़ोतरी ने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा कीं।

ट्रंप का दोहरा रवैया
ट्रंप के कार्यकाल में भारत-अमेरिका रिश्तों की तस्वीर विरोधाभासी रही। एक तरफ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते, "Howdy Modi" जैसे कार्यक्रमों में दोस्ती की बातें करते। दूसरी तरफ वे भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देते। ट्रंप बार-बार कहते थे कि अमेरिका, भारत से व्यापार घाटे (Trade Deficit) का शिकार है, और इसे कम करना उनकी प्राथमिकता है। यूरोप और यूक्रेन तक को उन्होंने अपील की कि भारत पर दबाव बनाने के लिए वे भी ऊँचे टैरिफ लागू करें। इससे स्पष्ट है कि ट्रंप का रवैया "दोस्ती भी, दबाव भी" वाला था।

भारत की रणनीति: समानांतर वार्ता और विकल्पों की तलाश
भारत ने अमेरिकी दबाव का जवाब सीधे टकराव से नहीं दिया, बल्कि एक "समानांतर वार्ता" (Parallel Negotiation) की रणनीति अपनाई। रूस के साथ तेल व्यापार - भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना जारी रखा। चीन और एशियाई देशों से रिश्ते - भारत ने RCEP जैसी चर्चाओं में सावधानी बरती, लेकिन व्यापारिक साझेदारी के नए विकल्प तलाशे। यूरोप के साथ FTA वार्ता - यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत तेज़ की गई। खाड़ी देशों से ऊर्जा साझेदारी - सऊदी अरब, यूएई और कतर के साथ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नए समझौते किए। एएससीओ और ब्रिक्स - इन बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल कर भारत ने यह संदेश दिया कि वह अकेला नहीं है।



भारत पर दबाव डालने की अमेरिकी कोशिशें
अमेरिका ने सिर्फ टैरिफ ही नहीं बढ़ाए, बल्कि कुछ और कदम भी उठाए: जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (GSP) खत्म करना - पहले भारत को अमेरिका में कुछ उत्पाद बिना शुल्क बेचे जाने की छूट थी, जिसे ट्रंप प्रशासन ने समाप्त कर दिया। हथियार सौदे का दबाव - अमेरिका में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत को चेतावनी दी। कूटनीतिक दबाव - यूरोपीय देशों और यूक्रेन तक को भारत के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश।

भारत की जवाबी रणनीति
भारत ने भी कुछ मोर्चों पर कड़ा रुख दिखाया। अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर "रिटैलियेटरी टैरिफ" लगाया। अमेरिका को यह संदेश दिया कि भारत भी ज़रूरत पड़ने पर अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगा। साथ ही, भारत ने बातचीत के रास्ते खुले रखे और कभी दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं किए। **दोस्ती के दावे और हकीकत**
ट्रंप और मोदी के रिश्तों को लेकर मीडिया में बार-बार "मजबूत दोस्ती" की बातें होती रहीं। बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए, जिनमें दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की तारीफ़ की। पर वास्तविकता यह रही कि ट्रंप का मक़सद सिर्फ अमेरिकी हितों की रक्षा करना था। भारत के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि अमेरिका की दोस्ती सिर्फ "लेन-देन" पर आधारित है।

वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति
इस टैरिफ वॉर ने भारत को यह

पर कौन आता है, यह राजनीतिक संकेतों से कहीं ज्यादा संसदीय कार्यप्रणाली और संविधानिक परंपराओं से जुड़ा मामला है। **चुनाव की प्रक्रिया**
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर इस निर्वाचक मंडल की संख्या 780 (543 लोकसभा + 237 राज्यसभा सदस्य) मानी जाती है। चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) का उपयोग होता है। पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, यानी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान कर सकते हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग (Cross Voting) और अमान्य मतपत्र (Invalid Votes) अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं।

2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव: नतीजों की झलक
इस बार मुकाबला था: सी.पी. राधाकृष्णन - राजग (NDA) उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी - विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का अनुमानित समीकरण: राजग (NDA) के पास: 427 वोट, विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के पास: 315 वोट, अन्य/निर्दलीय/छोटे दल: शेष वोट वास्तविक नतीजे: राधाकृष्णन को मिले: 452 वोट, सुदर्शन रेड्डी को मिले: 300 वोट अमान्य घोषित: 15 वोट, इस तरह राजग को अनुमानित समर्थन से 25 वोट ज्यादा मिले और विपक्षी खेमे के उम्मीदवार को तय समर्थन से 15 वोट कम मिले। **वोट अंतर के निहितार्थ**
राजग की अपेक्षा से अधिक ताकत: 25 अतिरिक्त वोट यह दिखाते हैं कि केवल राजग ही नहीं, बल्कि विपक्षी खेमे के सांसदों का भी विश्वास राधाकृष्णन पर रहा।

यह भाजपा की संसदीय प्रबंधन क्षमता का भी संकेत है। विपक्षी खेमे में दरारें: 'इंडिया' गठबंधन की एकता सवालों के घेरे में है। 15 वोट कम पड़ना और 15 अमान्य हो जाना दोनों ही विपक्षी रणनीति की कमजोरी का परिणाम हैं। क्रॉस वोटिंग की पुष्टि: विपक्ष के कई सांसदों ने राजग उम्मीदवार को वोट डाला यह केवल 'अंतरात्मा की आवाज़' नहीं बल्कि अंदरूनी असहमति का भी संकेत है। अमान्य मतपत्र: सवालों का अंवार मतदान से पहले सांसदों को मॉक ड्रिल के माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया समझाई गई थी। इसके बावजूद 15 वोट अमान्य हो गए। इससे यह सवाल उठते हैं: क्या सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले? क्या यह विपक्ष के भीतर असंतोष जताने का तरीका था? या फिर यह तकनीकी जानकारी की कमी या लापरवाही का परिणाम? अमान्य वोटों ने विपक्ष की छवि और अधिक कमजोर कर दी है। **विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की रणनीति की असफलता**
'इंडिया' गठबंधन ने यह चुनाव अपने एकजुट होने के प्रदर्शन के लिए लड़ा था। लेकिन नतीजे ने इसके बिल्कुल उलट संदेश दिया। अंतरात्मा की आवाज़ का नारा: विपक्ष ने सांसदों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने की अपील की थी। लेकिन यह नारा उन्हीं पर भारी पड़ गया। संचार और समन्वय की कमी: उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का चयन भी सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। कई विपक्षी दल चुनाव प्रचार या समर्थन में सक्रिय नहीं दिखे। सत्ता पक्ष का प्रबंधन कौशल : राजग ने न केवल अपने सांसदों को एकजुट रखा, बल्कि विपक्षी खेमे से भी समर्थन खींच लिया। क्रॉस वोटिंग: भारतीय राजनीति का पुराना खेल, भारतीय संसदीय इतिहास में क्रॉस वोटिंग नई



बात नहीं है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव—इंदिरा गांधी की रणनीति और क्रॉस वोटिंग ने वी.वी. गिरि को जीत दिलाई थी। कई उपराष्ट्रपति चुनावों में भी विरोधी दलों के सांसदों ने सत्ता पक्ष को वोट दिया है। इस बार भी क्रॉस वोटिंग ने ही नतीजे का अंतर बढ़ा दिया। **राजग की मजबूती का संदेश**
राजग में पकड़ - राधाकृष्णन की जीत ने दिखा दिया कि राजग की पकड़ संसद में बेहद मजबूत है। विपक्ष की कमजोरी का लाभ - राजग की विपक्ष की असहमति से फायदा हुआ। भविष्य की राजनीति पर असर - इस जीत से भाजपा और राजग को राज्यसभा और अन्य चुनावों में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। **भविष्य के राजनीतिक संकेत**
विपक्षी गठबंधन का भविष्य: यदि विपक्ष आपसी मतभेद और क्रॉस वोटिंग पर काबू नहीं पा सका, तो 2029 लोकसभा चुनाव तक इसकी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। 'इंडिया' गठबंधन को अब आत्ममंथन करना होगा। राजग की रणनीतिक बढ़त: इस नतीजे ने साफ कर दिया है कि राजग न केवल अपने साथियों बल्कि विपक्ष के अस्तुंए सांसदों तक पहुंच बनाने में सक्षम है।

इससे राष्ट्रपति और राज्यसभा से जुड़े आगामी चुनावों में भी इसका फायदा होगा। जनता के लिए संदेश: जनता के बीच यह छवि गई है कि विपक्ष केवल नाम भर का गठबंधन है, जबकि सत्ता पक्ष मजबूत और संगठित है। **आलोचनात्मक दृष्टिकोण**
कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि इस तरह के चुनावों में परिणाम पहले से तय होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत अधिक राजनीतिक संदेश के रूप में नहीं देखा चाहिए। लेकिन दूसरी ओर, वोटों के अंतर ने यह साबित कर दिया कि सत्ता पक्ष का प्रभाव केवल गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्षी खेमे पर भी पड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का परिणाम केवल एक संवैधानिक पद के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की गहराई में चल रही हलचलों का संकेतक है। राजग उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन की जीत तय थी, लेकिन 25 अतिरिक्त वोटों ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' अपनी असहमति और रणनीतिक कमजोरी की वजह से न केवल हार गया बल्कि और अधिक बिखरा हुआ प्रतीत हुआ। क्रॉस

वोटिंग और अमान्य वोटों ने इस हार को और भी करारा बना दिया। आने वाले समय में यह नतीजा विपक्ष के लिए आत्ममंथन और सत्ता पक्ष के लिए आत्मविश्वास का कारण बनेगा। लोकतंत्र में ऐसे चुनाव केवल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। **भारतीय राजनीति में नैतिकता बनाम व्यावहारिकता**
उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारतीय राजनीति में नैतिकता की अपील का कितना असर होता है। विपक्षी खेमे ने 'अंतरात्मा की आवाज़' का नारा दिया, लेकिन जब नतीजे आए तो यह नारा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। यह दर्शाता है कि संसदीय राजनीति में केवल आदर्शवाद से काम नहीं चलता, बल्कि व्यावहारिक राजनीति और मजबूत संगठन क्षमता की ज़्यादा अहमियत होती है। राजग की ओर से सांसदों को साधने और विपक्षी असंतोष को धुनाने की जो रणनीति अपनाई गई, वह पूरी तरह सफल रही। यह वही व्यावहारिक राजनीति है जिसे विपक्ष अब तक समझ नहीं पाया।

बंद खदानों को पाटना जरूरी: बरसाती पानी के भराव से हर पल मंडराता खतरा

-मकराना हादसा: बंद खदानों की लापरवाही का ताजा सबूत

राजस्थान को खनिज संपदा का गढ़ कहा जाता है। यहां का मरुस्थलीय भूभाग केवल रेत, रेगिस्तान और ऊंटों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहां की धरती में चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, जिप्सम, जिंक, तांबा और कई तरह के मूल्यवान खनिज भरे पड़े हैं। यही कारण है कि राजस्थान को खनिज की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन जहां यह खनिज उद्योग लाखों लोगों को रोजगार और सरकार को भारी राजस्व देता है, वहीं खनिज की अंधाधुंध प्रक्रिया और बंद खदानों को जैसी तरीके से न पाटने की वजह से लोगों की जान पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। खनिज के दौरान सरकार और विभाग की ओर से शर्त रखी जाती है कि खदान की लीज खत्म होने पर या खनिज उत्पादन बंद हो जाने पर उस खदान को मिट्टी, मलबे और पत्थरों से भरकर समतल किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि खदान मालिक तब तक नियमों का पालन करते हैं जब तक खदान से उन्हें मोटी कमाई होती रहती है। जैसे ही खदान में खनिज निकलना बंद हो जाता है, खदान को अधूरा छोड़कर मालिक किनारा कर लेते हैं। परिणामस्वरूप गहरे गड्डे खुले मुंह खड़े रहते हैं और बरसात का पानी भरते ही यह मौत के कुएं बन जाते हैं।

मकराना का उदाहरण और हालिया हादसा
नागौर जिले के मकराना का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहां से निकलने वाला सफेद संगमरमर ताजमहल सहित दुनिया की कई ऐतिहासिक इमारतों में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यही मकराना आज खदानों की लापरवाही के कारण हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। हाल ही में मकराना के चक डूंगरी रेंज के पीछे एक साथ आधा दर्जन खदानें ढह गईं। सौभाग्य से वहां उस समय कोई मजदूर या आम नागरिक मौजूद नहीं था, अन्यथा

बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने खान विभाग की नींद तोड़ी और विभाग ने अन्य बंद खदानों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल यही है कि हादसा होने से पहले विभाग क्यों नहीं जागता? **खनिज लीज की शर्तें और वास्तविकता**
सरकार जब किसी कंपनी या व्यक्ति को खदान का पट्टा या लीज देती है, तो उसमें साफ-साफ शर्तें लिखी होती हैं— खदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। काम खत्म होने पर या लीज की अवधि पूरी होने पर खदान को मिट्टी और मलबे से भरकर समतल किया जाएगा। आसपास के पर्यावरण, जल स्रोत और गांवों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इन शर्तों का पालन शायद ही कभी होता है। जब तक खदान से संगमरमर या खनिज की निकासी होती रहती है, तब तक मालिक सुरक्षा नियमों का दिखावाटी पालन करते हैं। जैसे ही खदान में उत्पादन कम हो जाता है या लीज खत्म होती है, वहां केवल गहरे और खतरनाक गड्डे बन जाते हैं।

राजस्थान के खनिज क्षेत्रों की स्थिति
राजस्थान के कई जिलों में खनिज के धरती का नक्शा ही बदल दिया है। मकराना (नागौर) - संगमरमर के लिए मशहूर, जहां ढेरों खदानें आज खतरनाक गहराई तक पहुंच चुकी हैं। सीकर - यहां की कई खदानें उत्पादन खत्म होने के बाद गहरे गड्डों के रूप में सूनी पड़ी हैं। अजमेर और ब्यावर - संगमरमर और ग्रेनाइट की खदानें, जिनमें सुरक्षा की अनदेखी अक्सर होती है। पाली - यहां खनिज से कई गांवों के आसपास जमीन धंसने और जलस्रोत सूखने की शिकायतें मिलती रहीं हैं। झुंझुनूर और बाड़मेर - यहां विभिन्न खनिजों के दोहन के बाद छोड़ी गई खदानें लोगों और पशुओं की जान के लिए खतरा बनी हुई हैं। इन खदानों की गहराई



इतनी बढ़ जाती है कि बरसात का पानी भरते ही यह तालाब जैसी स्थिति बना लेती है। फर्क इतना है कि तालाब में तैराकी की जा सकती है, जबकि खदानों में पानी के साथ तेज ढलान, फिसलन और गहराई होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या पशु गलती से गिर जाए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। **बरसाती पानी और खतरनाक भराव**
बरसात आते ही बंद खदानें पानी से भर जाती हैं। गहरे गड्डों में पानी का स्तर कई फीट तक पहुंच जाता है। यह पानी न केवल डूबने का खतरा पैदा करता है, बल्कि कई बार जहरीला भी हो जाता है क्योंकि इसमें खनिज अवशेष और रसायन घुल जाते हैं। बच्चे खेलते-खेलते इन गड्डों में फिसल जाते हैं। पशु चराई के दौरान पानी पीने आते हैं और फिसलकर डूब जाते हैं। कई बार मजदूर या राहगीर भी इसमें फंसकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। अखबारों में हर साल ऐसी खबरें आती हैं कि फलों जिले में बंद खदान में पानी भरने से बच्चों या युवाओं की मौत हो गई। **विभागों की लापरवाही**
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लीज की शर्तों में साफ लिखा है कि खदान को पाटना जरूरी है, तो फिर खान विभाग और जिला प्रशासन इसे लागू क्यों नहीं करता? असल में जब खदान चल रही होती है तो विभाग के अधिकारी जल्द कर खदानों को भरवा सकती हैं। लेकिन इसके लिए सख्त इच्छाशक्ति और ईमानदारी की जरूरत है।

होता है, उनकी दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है। खदान मालिक और विभाग दोनों की इस मिलीभगत का खासियाजा आम जनता को भुगताना पड़ता है। **पर्यावरणीय प्रभाव**
बंद खदानों को न पाटने से सिर्फ हादसे ही नहीं होते, बल्कि इसका गंभीर पर्यावरणीय असर भी पड़ता है— जल स्तर पर असर - गहरे गड्डों में बरसाती पानी भर जाने से आसपास के भूजल का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है। जमीन धंसना - अधूरी खदानें आसपास की जमीन को कमजोर बना देती हैं। कई बार गांवों और खेतों में जमीन धंसने के मामले सामने आते हैं। जहरीला पानी - खनिज और रसायनों के अवशेष पानी में घुलकर उसे जहरीला बना देते हैं। जो पीने योग्य नहीं होता। वन्यजीव और पशु हानि - जंगली जानवर और पालतू पशु इन खदानों में गिरकर अपनी जान गंवाते हैं। **खदान मालिकों की जिम्मेदारी**
खनिज से सबसे अधिक फायदा खदान मालिकों को होता है। वे खनिज बेचकर करोड़ों-अरबों रुपये कमाते हैं। ऐसे में उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि खदान खत्म होने के बाद उस गड्डे को भरवाएं और जमीन को फिर से सुरक्षित बनाएं। लेकिन हकीकत में वे जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर सरकार चाहे तो मालिकों की सिक्वोरिटी मनी या बैंक गारंटी जब्त कर खदानों को भरवा सकती हैं। लेकिन इसके लिए सख्त इच्छाशक्ति और ईमानदारी की जरूरत है।

उप मुख्यमंत्री ने आरडीटीएम 2025 के दूसरे दिन बी2बी मीटिंग्स और एक्सपो का किया शुभारम्भ

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। उप मुख्यमंत्री दिवा कुमारी ने फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 के दूसरे दिन शनिवार को बी.एम. बिड़ला कन्वेंशन सेंटर में बी2बी मीटिंग्स और एक्सपो का शुभारम्भ किया। उपमुख्यमंत्री दिवा कुमारी का पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियाड़ एवं FHTR के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री दिवा कुमारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस शानदार आयोजन के लिए पर्यटन विभाग FHTR को हार्दिक बधाई दी। दिवा कुमारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में अधिक से अधिक पर्यटक आएँ, यही हमारा ध्येय है। राज्य सरकार पर्यटकों



के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास कर रही है। दिवा कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन सुविधागत विकास कार्यों के लिए 5000 करोड़ रूपए का बजट खर्च किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय भी किये जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटक एप भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में मार्केटिंग का अत्यधिक महत्त्व है। राजस्थान की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग राज्य सरकार एवं पर्यटन विभाग कर रहा है। मीडिया एवं सोशल

मीडिया के माध्यम से राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करके ही हम पर्यटन क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर सकते हैं। इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग की आयुक्त रुक्मिणी रियाड़, एफएचटीआर प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला, एफएचटीआर महासचिव सीए वीरेंद्र एस. शेखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र एस. शाहपुरा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भिवाड़ी में किया, पर्यावरण एवं स्वच्छता, संबंधित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने शनिवार की अलसुबह खेरथल-तिजारा में भिवाड़ी के सेंट्रल पार्क एवं बाबा मोहन राम नगर वन का भ्रमण किया और शहरवासियों से संवाद कर उनकी आशाएँ, आकांक्षाएँ व समस्याएँ सुनीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भिवाड़ी को स्वच्छ, हरित एवं विकसित शहर बनाने के लिए आमजन से सहयोग का विशेष आह्वान किया।



सर्वप्रथम उन्होंने सेंट्रल पार्क में पहुंचकर नागरिकों से मिलकर उनके विचार साझा किए और स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। इसके बाद बाबा मोहन राम नगर वन का निरीक्षण किया गया, जो कि 102 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस नगर वन में मियावाकी पद्धति के माध्यम से अब तक 1 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जो क्षेत्र के पर्यावरणीय संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस दौरान बाबा मोहन राम नगर वन में वृक्षारोपण भी किया। नगर वन

की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने घर के बाहर कचरा पात्र का प्रयोग करे, कचरे का होम सेरीप्रेशन अवश्य करें और अंटो टिपर में उचित रूप से डालें। यादव ने कहा भिवाड़ी को एक स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित शहर बनाने के लिए प्रशासन एवं नागरिक मिलजुल कर काम करें। हर नागरिक का सहयोग ही देश को स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में सबसे बड़ी शक्ति बनेगा।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भिवाड़ी में लंबे समय से चल रही जलभराव समस्या के स्थायी समाधान के लिए सारेखुर्द बांध का भी निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का गहन अध्ययन करते हुए सम्बंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की ताकि समस्या का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर यादव ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से महात्मा गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आमजन

खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव - वन राज्यमंत्री

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर जिले के सोफिया पब्लिक स्कूल में आयोजित 69 वीं जिलास्तरीय विद्यालयी बास्केटबॉल व हैंडबॉल क्रीडा प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने संबोधन देते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें, खेल व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ-साथ सर्वांगीण विकास करता है। हमें पढ़ाई के साथ-साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलवर जिले ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की पहल पर इंदिरा गांधी स्टेडियम



में 7 करोड़ रूपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि जिले के हॉकी खिलाड़ियों की मांग पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल दिवस के अवसर पर प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में हमें 10 करोड़ की लागत के हॉकी एस्ट्रीफ़ मैदान की सौगत दी

है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल की अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए सीएसआर के माध्यम से बास्केटबॉल व हैंडबॉल के मैदानों के सुदृढीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों से प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक स्तर पर 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने की अपील की।

जयपुर : बारिश के बाद हेरिटेज निगम ने की फॉगिंग कार्य की तेज गति

-हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने दिए निर्देश

जयपुर। बारिश के बाद आमजन को बीमारियों से बचाने के लिए हेरिटेज निगम प्रशासन युद्धस्तर पर फॉगिंग अभियान चला रहा है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल के निर्देश के बाद निगम की स्वास्थ्य शाखा ने दूसरे चरण के तहत अब तक तकरीबन 80 वार्डों में फॉगिंग कार्य करा दिया है। फॉगिंग कार्य हूपर के माध्यम से वार्डों की कालोनियों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य शाखा की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सोनिया अग्रवाल के नेतृत्व में टीम घर घर जाकर आमजन से मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के तरीके भी बता रही है। इसके अलावा वार्ड जगहों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, जिससे कि मच्छर का लार्वा नहीं पनपे। इसके अब बारिश के बाद मौसमी जनित बीमारियों के प्रकोप से आमजन को बचाने के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल के निर्देश पर दूसरा चरण 22 अगस्त से शुरू किया जा चुका है, अब तक



केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भिवाड़ी में लंबे समय से चल रही जलभराव समस्या के स्थायी समाधान के लिए सारेखुर्द बांध का भी निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का गहन अध्ययन करते हुए सम्बंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की ताकि समस्या का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर यादव ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से महात्मा गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आमजन

की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने घर के बाहर कचरा पात्र का प्रयोग करे, कचरे का होम सेरीप्रेशन अवश्य करें और अंटो टिपर में उचित रूप से डालें। यादव ने कहा भिवाड़ी को एक स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित शहर बनाने के लिए प्रशासन एवं नागरिक मिलजुल कर काम करें। हर नागरिक का सहयोग ही देश को स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में सबसे बड़ी शक्ति बनेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को शीघ्र मिलेगी राहत

- जिला कलक्टर के निर्देश पर अवकाश के दिन भी अधिकारियों ने लिया फसल नुकसान का जायजा

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फसल खराबे से प्रभावित किसानों को हर संभव राहत शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेने के निर्देश जारी किए। कलक्टर डॉ. सोनी के निर्देशों पर शनिवार को उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों ने वर्षा प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फसल खराबे से प्रभावित किसानों को हर संभव राहत शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेने के निर्देश जारी किए। कलक्टर डॉ. सोनी के निर्देशों पर शनिवार को उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों ने वर्षा प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि

बीमा अथवा मुआवजे से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएँ, जिससे शीघ्र ही राहत वितरण की कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। अधिकारियों ने किसानों एवं ग्रामीणों को संवाद करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई हेतु राहत कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री एवं वन राज्य मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को किया सम्मानित



जयपुर (रॉयल पत्रिका)। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर एवं वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर जिला स्थित प्रताप ऑडिटोरियम में पहल संस्थान के तत्वावधान में आयोजित सेवा सम्मान, शैक्षिक सेवा और सामाजिक सेवार्थ सम्मान समारोह में शिरकत कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि समाज में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक ही वह कड़ी होती है जो विद्यार्थी को निखारकर उसके भविष्य को संवारता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण ही अब सरकारी विद्यालयों का परिणाम निजी विद्यालयों से अच्छा आने लगा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकगणों के कठिन परिश्रम से राजस्थान ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में 11वें स्थान से जम्प कर अब तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु निरन्तर

सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकगण संकल्प ले कि पानी की एक-एक बूंद की भीमत समझते हुए पानी व्यर्थ नहीं बहाएँ, विद्यालयों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में हमारे राजस्थान के शूरवीरों की गाथाओं को विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने अलवर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में 3 करोड़ की राशि से विकास कार्य कराए जाने पर शिक्षा मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षा का अच्छा वातावरण प्रदान करने लिए सकारात्मक प्रयास किए हैं। उन्होंने भामाशाही एवं शिक्षकों द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्यों में सहयोग करने एवं गरीब बच्चों को उनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता करने पर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को शिक्षा का अच्छा वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से ई-लाइब्रेरियों

का निर्माण कराया है जिनमें 106 ई-लाइब्रेरी सरकारी विद्यालयों में बनी है। साथ ही शहर में तीन और ई-लाइब्रेरी बनाने के साथ जिलेभर 'एन-जन का अभियान बनकर उभरा है। उन्होंने आह्वान किया कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों का लालन-पालन करती है उसी प्रकार हम पौधा का संरक्षण करें तो आने वाले समय में पौधा वृक्ष का रूप लेकर पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने पर विभिन्न व्याख्याता, अध्यापक एवं प्रधानाचार्या को सम्मानित किया गया।

जीएसटी स्लैब बदलने से कई उत्पाद सस्ते होंगे एमआरपी रेट होगी कम



जयपुर (रॉयल पत्रिका)। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे के द्वारा जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से होने वाले बदलाव के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के घटते हुए दामों पर निगरानी एवं शिकायत करने को लेकर स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठन, संगठनों के साथ प्रत्यक्ष एवं वीसी मोडु के जरिए एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें हाल ही सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव के कारण कीमतों में हुई कमी की निगरानी करने एवं एमआरपी पर संशोधित स्टीकर लगाने और नई रेट प्रिंटेड करवाने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सुझाव रखा। उन्होंने सभी से यह अपील की कि अपने स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली हेल्पलाइन नंबर

1915 का व्यापक प्रचार किया जाए और अधिक मूल्य वसूली होने पर शिकायत की जाए। उन्होंने लोकल स्तर पर समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं होल्डिंग के जरिए इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाने का परामर्श दिया। इस अवसर पर केंज्यूमर एक्शन एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष विजेंद्र प्रकाश हलवल ने सचिव की दूरदृष्टि एवं अभियान की सराहना करते हुए भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अवागत कराया कि वह मीडिया का सहारा लेकर अभियान को जन-जन तक पहुंचाएंगे। मीटिंग में डॉ. अनंत शर्मा अध्यक्ष सीसी आई, सुश्री पुष्पा गरिमा, सोविता देशपांडे आदि भी ने अपने विचार रखे।

संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक हुई आयोजित



जयपुर (रॉयल पत्रिका)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक शनिवार को जोधपुर जिले में पाट रोड़ स्थित पंचायत समिति लूणी के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जल जीवन मिशन की योजनाओं एवं पैरी अर्बन योजनाओं की प्रगति पर व्यापक चर्चा हुई। पटेल ने कहा यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार समुचित जलापूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना और जवाई पुनर्भरण योजना जैसे ऐतिहासिक कार्यों को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने पेरीफेरी अर्बन एरिया प्रोजेक्ट में वंचित गांवों को जोड़ने, राजस्व विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर जोधपुर के भावी विस्तार को ध्यान में रखकर सर्वे कार्य पूर्ण करने के

निर्देश दिए। उन्होंने माणकलाव-दईजर बनाइ 37 गांवों की पेयजल परियोजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को तय समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पटेल ने बन्द एवं खराब ट्यूबवेल को रिपेयर कर शीघ्र प्रारंभ करने, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के रिप्लेसमेंट के प्रस्ताव बनाने और विभागीय अधिकारियों को फील्ड में औचक निरीक्षण कर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा अवैध कनेक्शन काटें और कनेक्शन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवायें। संसदीय कार्य मंत्री ने हेडवर्क्स पर 24 घंटे कार्मिक लगाने, नदी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष कार्य योजना बनाने, जल जीवन मिशन के कार्यों को तय समयावधि में पूर्ण करने और हेण्डपंप और ट्यूबवेल संबंधी प्रस्ताव शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय उच्च अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाई

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी। संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनांतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के लिए यह अवसर दे रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि विभाग द्वारा पूर्व में 14 सितंबर निर्धारित की गई थी। मोदी ने बताया कि इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निःशुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाने की पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाया जाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर CM Anuprati Coaching Icon पर क्लिक कर CM Anuprati Coaching Scheme का चयन कर ड्रापडाउन में से Student के विकल्प पर जाकर अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक नम्बर		रॉयल पत्रिका
विजली फॉल्ट के लिए		
टोल फ्री नंबर	18001806507	जलदाय कार्यालय
वॉट्सएप नंबर	9414037085	फायर डिग्रेड
कन्ट्रमर केयर	2203000	
आईडीआरएस	1912	
पानी के लिए		
जलदाय कार्यालय	2706624	
फायर डिग्रेड	2747400	
मेडिकल इमरजेंसी के लिए		
एंबुलेंस	102/108	
एसएमएस इमरजेंसी	2518333	
महिला चिकित्सालय	22610616	
जनना हॉस्पिटल	22378721	
SDMH	22574189	
SMS ब्रॉड बैंक	22518222	
कल्याण ब्रॉड बैंक	22721771	
पुलिस की मदद के लिए		
साइबर क्राइम	1930/2360094	
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38	
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098	
महिला हेल्पलाइन	1090	
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	
घायल पशुओं के लिए		
नगर निगम	2747400	
वर्ड बाइक	9887345580	
हेल्प इन सफरिंग	8107299711	
जनमंच टूरट	7230055800	
पशु चिकित्सालय	2747400	

राष्ट्रीय लोक अदालत में दशकों पुराने प्रकरणों का मौके पर ही हुआ निपटारा

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल सदस्य राजेश कुमार दड़िया एवं माननीय सदस्य महेन्द्र लोढा की बैच में वर्षों पुराने कई प्रकरणों का निस्तारण होने से पक्षकारों के चेहरों पर खुशी लौट आयी। राजस्व मंडल में चिन्हित 495 प्रकरणों में से 419 राजस्व प्रकरण लोक अदालत की भावना से निस्तारित किये जा सके। लोक अदालत में 32 वर्ष पुराने 5 प्रकरण समझाइश के आधार पर निस्तारित किये गये। इन प्रकरणों में राम कल्याण, सत्यनारायण अग्रवाल बनाम महावीर प्रसाद, जगदीश प्रसाद अग्रवाल गांव बहरावंडा खुर्द तहसील खंडार



जिला सवाईमाधोपुर प्रमुख रहा। इन पक्षकारों को माननीय निबन्धक महावीर प्रसाद, सदस्यगण व बार अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजावत ने आपसी राजीमानी से प्रकरणों का निस्तारण करने पर मालाएँ

पहनाकर शुभकामनाएँ दीं। इसी प्रकार मंडल में 20 वर्ष से अधिक पुराने 15 राजस्व प्रकरण आपसी समझाइश के आधार पर निस्तारित किये।

कांग्रेस का तीन दिवसीय संगठन सर्जन प्रशिक्षण अभियान 16, 17 व 18 सितंबर को दादाबाड़ी में शुरू होगा

चुरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडोलिया हाउस चुरू में पंखा रोड स्थित दादाबाड़ी में आगामी 16, 17 व 18 सितम्बर को तीन दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण अभियान के तहत आवासीय शिविर की पूर्व तैयारी हेतु बैठक का आयोजन किया गया। चुरू जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष संजय दीक्षित ने बताया कि शिवर का उद्घाटन लोकप्रिय युवा सांसद राहुल कर्खा करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडोलिया, विशिष्ट अतिथि सुभाषक विधायक मनोज मेघवाल, राजस्थान सेवादल के अध्यक्ष हेमसिंह शेखावत होंगे। चुरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इन्द्राज खिवड कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तीन दिवसीय शिविर में तारानगर वरिष्ठ विधायक नरेन्द्र बुडानिया, सरदारशहर विधायक अनिल



शर्मा, रतनगढ़ विधायक पुसाराम गोदारा, सादुलपुर पूर्व विधायक कृष्णा पुनिया, राजस्थान महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष रिहाना रियाज, राजस्थान वकफ बोर्ड के चेयरमैन खानु खान बुधवाली, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल प्रभारी ज्योति खन्ना, अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल की मुख्य प्रशिक्षक मधु गुरूंग, प्रदेश से प्रशिक्षक रामभरोसी सैनी, सेवादल के जोन प्रभारी कमल कल्ला, संभाग प्रभारी विमल भाटी सहित अनेक नेता

मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेंगे। आज की बैठक में शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष असलम खोखर, चुरू जिला अग्रिम संगठन प्रभारी जमील चौहान, चुरू जिला सेवादल उपाध्यक्ष जगदीश धनवंशी, सेवादल जिला प्रवक्ता गोपाल बिजाराणिया, पार्षद विमल शर्मा, संजय भाटी, आबिद जाबासरिया, आरिफ खान रिसालदार, एडवोकेट अनिस खान, महबुब कुरेशी, सोनू नाई सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कर्नल बैसला की जयंती पर प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित

कर्नल बैसला की जीवन यात्रा समाज को नई दिशा देने वाली रही- भड़ाना

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक, समाज सुधारक एवं शिक्षा चेतना के अग्रदूत स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जन्म जयंती के अवसर पर रविवार को केकड़ी में भव्य भामाशाह एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक शत्रुघ्न गौतम, प्रधान होनहार सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में समाजसेवकों का भी भाग रहा। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जीवन प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अपने जीवन को समाज की उन्नति और पिछड़े वर्गों की आवाज को ताकत देने के लिए समर्पित कर दिया। गुर्जर समाज के हक और अधिकार को लड़ाई को शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संगठनात्मक ढंग से आगे बढ़ाया। भड़ाना ने कहा कि बाबा साहब बैसला ने पढ़ी-लिखी मां, कर्ज मुक्त समाज जैसे नारों



के माध्यम से समाज को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि कर्नल बैसला ने समाज को यह विश्वास दिलाया कि यदि हम एकजुट होकर शिक्षा और संगठन को प्राथमिकता दें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाएगी। उनसे हमें सीख लेनी होगी कि शिक्षा, अनुशासन और सेवा भाव समाज के विकास की धुरी हैं। मैं बैसला जी के विचारों को धरातल पर साकार करने हेतु 15 वर्ष सामाजिक इमरजेंसी लगाने एवं फ़िजूल खर्च बंद करने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि बाबा

साहब बैसला ने गुर्जर समाज को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक चेतना से जोड़ा। इस दिशा में जो भी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी, वे उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएंगी। उन्होंने आह्वान किया कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई जाए। कार्यक्रम में समाज के भामाशाहों, कार्यकर्ताओं एवं प्रतिभावान युवाओं का सम्मान किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कर्नल बैसला के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समाज को संगठन, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया।

दीपावली से पूर्व सुधरेंगी शहर की सड़कें, ऊंची होगी केसरबाग पुलिया देवनाणी

बोराज सहित 12 तालाबों की पाल होगी मजबूत- देवनाणी



अजमेर (रॉयल पत्रिका)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाणी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दीपावली से पूर्व शहर की सभी सड़कें सुधारी जाएं। केसरबाग पुलिया को ऊंचा और चौड़ा करने का प्रस्ताव 15 दिन में तैयार किया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग बोराज सहित शहर के 12 तालाब व नदियों को मजबूत करने के प्रस्ताव तैयार करें। इन सभी का अतिशीघ्र सक्षम मंजूरी दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाणी ने शुक्रवार को संकेत

हाऊस में जिला प्रशासन, एडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों की बैठक ली। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि शहर में बोराज जैसे 12 तालाब हैं। इन सभी की पाल काफी समय पूर्व बनी है। ज्यादा बारिश आने की दशा में क्षतिग्रस्त हो सकती है। आगामी बारिश से पूर्व बोराज, आम्बा नाडी, माकड़वाली सहित इन सभी 12 तालाबों की पाल सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एडीए से समन्वय कर मजबूत करने के प्रस्ताव तैयार करें।

भाजपा की सेवा पखवाड़े की जिला कार्यशाला -पूर्व नेताप्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के चुरू आवास पर संपन्न हुई

चुरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र सिंह राठौड़ के आवास पर भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़े की जिला कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व नेताप्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुधार, विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वन्दना आर्य, पूर्व विधायक अभिनेष महर्षि पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल, विधानसभा प्रत्याशी सुमित्रा पुनिया, जिला महामंत्री चन्द्रराम गुरी, प्रधान दीपचन्द राहड़, प्रधान मधुसुदन राजपुरोहित, प्रधान विनोद देवी पुनिया उपजिला प्रमुख महेन्द्र न्योल, नरेश सहारण, मंचस्थ रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के



कार्यकर्ताओं के संस्कार में सेवा सुशासन एमम राष्ट्र प्रेम है। उन्होंने कहा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है और गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्यकारक कार्य है। कार्यक्रम का आरंभ भारत माता, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर वृष्टि अर्पित व वंदे मातरम से हुआ वहीं कार्यक्रम का समापन जन गण मन से हुआ। सभी वक्ताओं ने

कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नरेन्द्र काछवाल, मोहनलाल खारड़िया, फतेह चंद सोती, जिला मंत्री दीन दयाल सैनी, निकिता गुर्जर, सत्तार खान, अनिता जोशी, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, धर्मेन्द्र राकसिया खडोलिया, दिनेश लाटा, बजरंग गुर्जर, भीमराज, रवि दायीच सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत टोंकवासा में जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित

-सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अंतर्गत धनराज बरगोट को 5 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र जारी

इंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक आमजन को योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य अनुरूप आयोजित की जा रही जिला कलक्टर की रात्रि चौपालों में परिवेदनाओं के समाधान के साथ योजना अंतर्गत पात्र लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्राम पंचायत टोंकवासा रात्रि चौपाल आयोजित हुई। पंचायत समिति आसपुर की ग्राम पंचायत टोंकवासा के राकवीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंकवासा में आयोजित रात्रि चौपाल में सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर धनराज बरगोट को 5 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र जारी कर लाभान्वित किया गया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने पेंशन शुरू करवाने, टोंकवेष महादेव तक सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने, आंगनवाड़ी केंद्र



टोंकवासा द्वितीय में आशा सहयोगी के रिक्त पद पर चयन करवाने, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत शेष कार्य पूर्ण करवाने, बरसाती पानी के जल निकासी करवाने, मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटवाने, सड़क का पेचवर्क करवाने सहित अन्य परिवेदनाओं को लेकर उपस्थित हुए तथा ग्रामीणों ने एक-एक कर जिला कलक्टर के समक्ष परिवेदनाएं प्रस्तुत की एवं जिला कलक्टर ने आत्मीयता पूर्वक एक-एक कर परिवेदनाओं सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए

नियमानुसार त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इससे पूर्व सामाजिक अधिकारी ने पालनहार योजना, पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी दी वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी ने निःशुल्क शिक्षा, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शन योजना की विस्तृत जानकारी दी। इसी प्रकार अन्य विभाग अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभाग से संबंधित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह: जागरूकता सेमिनार आयोजित



बीकानेर (रॉयल पत्रिका)। विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह के तीसरे दिन शुक्रवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग की ओर से सिंधिसिस कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। मानसिक रोग विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. गोपाल गोयल ने बताया कि विद्यार्थियों को आत्महत्या रोकथाम के उपाय, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा तनाव प्रबंधन पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान विद्यार्थी तनाव, दबाव और असफलता से टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में धैर्य और सकारात्मक सोच ही रास्ता दिखाती है। उन्होंने

कहा कि नियमित व्यायाम, योग, समय प्रबंधन, पर्याप्त नींद और परिजनों तथा मित्रों से विचारों को साझा करना तनाव कम करने में सहायक है। डॉ. मनीषा चौधरी ने आत्महत्या रोकथाम के क्वीआर मॉडल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मॉडल एक गेटकीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो आम लोगों से लेकर पेशेवर तक को आत्महत्या की आशंका वाले व्यक्ति की मदद करना सीखता है। इस दौरान एनएमएचपी के सीआरए विनोद कुमार पंचरिया, नरिसिंग स्टाफ राजीराम ने भी विचार रखें तथा विद्यार्थियों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने तथा कठिन परिस्थितियों में निराश न होकर मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया। संस्थान के प्रवीण शर्मा ने आभार जताया।

हज़रत शहीद पीर दुलेशाह बाबा र.अ.के उर्स चोटिला मेला में शिरकत के लिए सांसद इमरान मसूद को दिया निमंत्रण

मोहम्मद यासीन पाली (रॉयल पत्रिका)। दिल्ली में सहायपुर सांसद इमरान मसूद को पाली विधायक भीमराज भाटी और सदर अमजद अली रंगरेज ने पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े चोटिला मेले का निमंत्रण पत्र भेंट किया। सांसद इमरान मसूद ने विश्वास दिलाया कि वह इंशाअल्लाह मेले में जरूर



शिरकत करेंगे। इस मौके पर पाली विधायक भीमराज भाटी, सदर अमजद अली रंगरेज, जिज्ञान अली रंगरेज और सद्दाम हुसैन, अनवर मोयल मौजूद रहे।

कार्यकर्ताओं के संस्कार में सेवा सुशासन एमम राष्ट्र प्रेम है। उन्होंने कहा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है और गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्यकारक कार्य है। कार्यक्रम का आरंभ भारत माता, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर वृष्टि अर्पित व वंदे मातरम से हुआ वहीं कार्यक्रम का समापन जन गण मन से हुआ। सभी वक्ताओं ने

नैनो उर्वरक उपयोग महाअभियान के अंतर्गत फसल विचार गोष्ठी का आयोजन

प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना होगा- भागीरथ चौधरी

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था (इफको) द्वारा नैनो उर्वरक उपयोग महाअभियान के तहत राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएसएसए), अजमेर में एक दिवसीय फसल विचार गोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कुल 351 प्रगतिशील किसान शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, भागीरथ चौधरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय इफको निदेशक, नई दिल्ली, राम निवास गढ़वाल ने की। इस अवसर पर डॉ. विनय भारद्वाज, निदेशक, एनआरसीएसएसए, अजमेर, डॉ. धर्मेन्द्र सिंह भाटी, अध्यक्ष, केवाई अजमेर, सुधीर मान, राज्य विपणन



प्रबंधक, इफको राजस्थान, मदन गोपाल चौधरी, अध्यक्ष, केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर, डॉ. ए.पी. सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, इफको जयपुर, निर्भय चौधरी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, इफको जयपुर, अमित कुमार, आर.एम.ई. इफको एमसी जयपुर, डॉ. रमाकांत शर्मा, इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उप केंद्र अजमेर तथा डॉ. सुबोध सैनी, वरिष्ठ पशु अधिकारी, अजमेर सहित अजमेर जिले के सभी इफको आम

सभा सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपने उद्घोषण में माननीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने किसानों से संतुलित उर्वरकों के साथ-साथ नई कृषि तकनीकें जैसे नैनो उर्वरक और ड्रोन तकनीक को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि "मानव, पृथ्वी और समूचा ब्रह्मांड पंचतत्वों से निर्मित हैं, अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना होगा।"

स्वदेशी अपनाकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं कैडेट- देवनाणी

-रंगांग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन



अजमेर (रॉयल पत्रिका)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाणी ने स्वदेशी के साथ राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवा जोश की सक्रिय भागीदारी बेहद अहम है। देवनाणी ने कहा कि भारत आज सभी मोर्चों पर आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है। सीमाओं की रक्षा का मसला हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर परचम फहराने का, देश इन दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित एनसीसी कैडेट्स वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाणी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट्स के महत्वपूर्ण भूमिका है। देश का सबसे बड़ा युवा संगठन होने के नाते एनसीसी कैडेट्स पर ज्यादा जिम्मेदारी है। वह स्वदेशी को स्वीकार करें। देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने की सोच

को बढ़ावा दें, राष्ट्र की सेवा करें। इससे 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने। अपने उद्घोषण में उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को संस्कार के साथ भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का अनुसरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय के साथ ही हम विश्व में महान बन सकते हैं। विश्व में अपनी-अपनी धरा को किसी भी देश में माता नहीं कहा जाता, जिस प्रकार माता अपने पुत्र का लालन-पालन कर पोषण करती है। ठीक उसी प्रकार भारत माता हम सबका लालन-पालन कर पोषण कर रही है। इसकी सुरक्षा करना, संस्कृति को बचाए रखना, परंपराओं का अनुसरण करना तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने अपने उद्घोषण में एनसीसी कैडेट्स का उत्साह वर्धन करते हुए कैम्प में आए सभी विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी। इससे देश का अच्छा नागरिक तैयार होने पर भारत उन्नति और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।

राजकीय आईटीआई में प्रवेश 14 सितंबर से

चुरू (रॉयल पत्रिका)। जिले की चुरू व सरदारशहर राजकीय आईटीआई में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 14 सितंबर, 2025 से शुरू हो रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संस्थान चुरू उपनिदेशक नेहा सैनी ने बताया कि कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अधीन राजकीय व प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त रही सीटों पर सीधे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी संस्थान से व्यवसायवार रिक्त सीटों की सूचना प्राप्त कर राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल

एसएसओ अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से 14 सितंबर से 25 सितंबर, 2025 तक प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के फ्रिंट मय योग्यता दस्तावेज यथा अंकतालिका, मूल निवास, जाति प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड आदि मूल दस्तावेज तथा फोटो प्रति आईटीआई में 26 सितंबर, 2025 तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि संस्थान में प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट सूची संस्थान नोटिस बोर्ड पर 27 सितंबर, 2025 को लगाई जाएगी। संस्थान स्तर पर जारी मेरिट के

आधार पर समस्त श्रेणी वरीयता के अनुसार निर्धारित फीस (3400 रुपए) 29 सितंबर, 2025 को जमा करवानी होगी। छात्राओं का प्रशिक्षण निःशुल्क होगा (सभी का अवधान द्रव्य राशि 1000 रूपये होगा)। प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 सितंबर, 2025 को 14 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। प्रवेश हेतु योग्यता 8वीं, 10 वीं पास होना जरूरी है। किसी प्रकार की सहायता हेतु हेल्प डेस्क नम्बर 01562-253280 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना: औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले पांच इंटरन

बीकानेर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले इंटरन के कार्यस्थल का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पांच इंटरन अनुपस्थित मिले। एक इंटरन लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के बावजूद फर्जी तरीके से उपस्थित अपलोड करना पाया गया। इसके मद्देनजर संबंधित का बेरोजगारी भत्ता बंद करते हुए वसूली अथवा अन्य नियम संगत कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की गई। उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक हरगोबिंद मित्तल ने बताया कि योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले



प्राथियों को सरकारी विभागों में प्रतिदिन चार घंटे की इंटरशिप करनी होती है। शुक्रवार को श्रीद्वारगढ़ ब्लॉक स्थित राजकीय विद्यालयों में इसका औचक भौतिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि श्रीद्वारगढ़ के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सात में से पांच इंटरन अनुपस्थित मिले। इनमें भरत

राम पुत्र केशरा राम के कई माह से अनुपस्थित होने के बावजूद फर्जी उपस्थिति बनाकर अपलोड किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान भरत राम का बेरोजगार भत्ता अविश्लेष्य बंद कर दिया गया पूर्व में भत्ते के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली अथवा कानूनी कार्यवाही नियमानुसार प्रस्तावित की जाएगी।



करिश्मा तन्ना ने स्कूप की शूटिंग के पहले दिन को किया याद

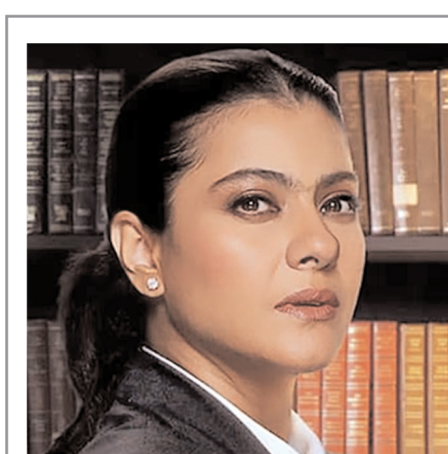


अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने अपनी सुपरहिट वेब सीरीज स्कूप के सेट से पुरानी यादों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर सेट से कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'नॉस्टैल्जिया! स्कूप के सेट पर पहला दिन... ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। घबराहट, उत्साह, बार-बार रिहर्सल और मन में एक आवाज जो कह रही थी, यह कुछ खास होने वाला है। यह सफर कितना शानदार रहा। पहले दिन की बेचैनी से लेकर उन यादों तक, जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगी। इस अध्याय, इसमें शामिल लोगों और साथ में बनाए गए जादू के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। इसी के साथ ही अभिनेत्री ने डायरेक्टर हंसल मेहता, नेटफ्लिक्स और पूरी टीम को धन्यवाद दिया। यह सीरीज साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। सच्ची घटना पर आधारित यह सीरीज पत्रकार जिन्ना चोरा की किताब बिहैंड बार्स इन बायकुला-माई डेज इन प्रिजन पर आधारित है। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित इस सीरीज में करिश्मा तन्ना ने पत्रकार जागृति पाठक की भूमिका निभाई है, जिन पर पत्रकार ज्योतिर्मयी डे की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। यह सीरीज मीडिया के काम करने के तरीके, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ और मीडिया में व्यवसाय के दखल जैसे मुद्दों को दर्शाती है। इस सीरीज ने करिश्मा को गंभीर और कहानी-केंद्रित किरदारों की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। दर्शकों और समीक्षकों ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी। करिश्मा तन्ना छोटें पदों से लेकर बड़े पदों तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने साल 2001 में टीवी शो क्वॉकि सास भी कभी बहू थी से अपने करियर की शुरुआत की। वह बाल वीर, नागिन 3, और कयामत की रत जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं।



डायना पेंटी ने बताया, 'डू यू वाना पार्टनर' शो में उन्हें क्या सबसे ज्यादा भाया

वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इसमें डायना पेंटी, तमन्ना भाटिया, श्वेता तिवारी, जावेद जाफरी, नकुल मेहता, नीरज काबी, सूपी मोतीवाला और रणविजय सिंह जैसे सितारे हैं। 'डू यू वाना पार्टनर' की रिलीज से पहले डायना पेंटी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीरीज की खासियत के बारे में बताया। डायना ने यह भी रिवाज किया कि उन्होंने इस सीरीज को क्यों चुना। अभिनेत्री ने बताया कि इसकी स्क्रिप्ट को सुनने के बाद काफी आकर्षित हुईं। डायना पेंटी ने कहा, दोनों लड़कियों को दोस्ती ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि मैं रियल लाइफ में ऐसा करती। मुझे लगा कि यह बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत ही वास्तविक है। मैं भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ ऐसे ही बातचीत करती या बस वे चीजें करती, जो इसमें लिखी थीं। कुछ भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं लिखा गया था। बस बहुत ही रोजमर्रा की और बहुत ही वास्तविक कहानी, जिस तरह से वे साथ घूमती हैं, साथ में पार्टी करती हैं। उन्होंने साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया है, उनकी कठिनाइयां, झगड़े, बहस, सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक था और हमारी दोस्ती में जो हम देखते हैं, उसके बिल्कुल अनुरूप था। डू यू वाना पार्टनर में दो सहेलियों की कहानी है, जो खुद का अल्कोहल ब्रांड लॉन्च करने के लिए पार्टनर बन जाती हैं। डायना ने आगे कहा, यह मेरे लिए एक ताजगी भरी बात थी क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरा मतलब है कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं हाल ही में किसी ऐसे शो या फिल्म के बारे में नहीं सोच सकती, जिसमें दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों की दोस्ती शो या फिल्म का मुख्य पहलू हो। यह तथ्य कि दोनों लड़कियां ऐसे युग में यह नया बिजनेस शुरू कर रही हैं, जहां स्टार्टअप ही सब कुछ है। पिछले कुछ समय में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए यही सब बातें थीं, जिन्होंने मुझे वास्तव में इस स्क्रिप्ट की ओर आकर्षित किया।



मैं अपनी हर फिल्म की मालिक हूँ, फिर

चाहें हिट हो या फ्लॉपबॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का कहना है कि वह अपनी हर फिल्म को पूरी तरह से अपनाती हैं। फिर चाहे वह सुपरहिट हो जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम या फिर ऐसी फिल्में जो ज्यादा नहीं चलें जैसे गुंडाराज और हलचल। वह जल्द ही सीरीज द ट्रायल के सीजन 2 में नजर आएंगी। अपनी फिल्मों को लेकर काजोल का बयान: 1992 में फिल्म बेखुदी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली काजोल ने बताया, मैं अपने करियर में कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगी। उन्हें उन फिल्मों पर भी गर्व है, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुईं। उन्होंने कहा, मेरी हर फिल्म ने मुझे कुछ सिखाया है। मैंने हर बार अपना 100 प्रतिशत दिया है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने कैमरे के सामने कभी बेईमानी नहीं की। काजोल ने अपने 30 साल के करियर के लिए आभार जातते हुए कहा, मैं आज भी प्रासंगिक हूँ, यह मेरी किस्मत है। कई प्रतिभाशाली लोग हैं, जो शायद मेरे जितने भाग्यशाली नहीं रहे।

मेरा फिल्मी कपूर परिवार से कोई लेना-देना नहीं



मेरा फिल्मी कपूर ने करियर की शुरुआत से अब तक हमेशा अपने किरदारों में विविधता और चुनौती को प्राथमिकता दी है। 'चंडीगढ़ करे आशिकी' में ट्रांसवुमन का किरदार हो या 'शुद्ध देसी रोमांस' की आजाद लड़की, वाणी ने कभी आसान रह नहीं चुनी। इस बार उन्होंने ओटीटी डेब्यू में एक यंग लेकिन मजबूत इमोशनल ग्राउंड वाली पुलिस आफसर रिया थॉमस का किरदार

निभाया है। इस बातचीत में वाणी बताती हैं कि कैसे कैमरे के सामने वो फीलिंग्स भी असली हो गईं, जो सिर्फ स्क्रिप्ट में लिखी थीं। कैसे 'कपूर' सरनेम के साथ नेपोटिज्म के आरोपों से लड़ते हुए उन्होंने खुद को साबित किया और क्यों उन्होंने कभी पैसा या फेम नहीं बल्कि सिर्फ सही काम को चुना।

रिपिटेशन से बचना चाहती थी वाणी कपूर ने कहा, इससे पहले कभी किसी वेब सीरीज में काम नहीं किया था। यह ऑफर जब आया तो मन में पहली बात यही आई कि अब ओटीटी पर आ रही हूँ तो कुछ बिल्कुल अलग और नया करना चाहिए। हर बार खुद से यही उम्मीद करती हूँ कि कुछ नया लेकर आ सकूँ, अपने लिए और दर्शकों के लिए भी। रिपिटेशन से बचना चाहती हूँ। मेरी हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश रही है। फिर चाहे रेड 2 में हाउसवाइफ का किरदार हो, चंडीगढ़ करे आशिकी में एक ट्रांसवुमन का या शुद्ध देसी रोमांस में जयपुर की एक आजाद ख्याल लड़की का।

कपूर हूँ लेकिन नेपो प्रोडक्ट नहीं

लोग सोचते हैं कि मैंने शुद्ध देसी रोमांस के लिए ऑडिशन दिया और आसानी से फिल्म मिल गई। ऊपर से मेरा सरनेम कपूर है तो लोग सोचते हैं मैंने नेपोटिज्म प्रोडक्ट हूँ। मेरा फिल्मी कपूर परिवार से कोई लेना-देना नहीं। मैं दिल्ली से बहुत सकुचा-सकुचा के अकेले मुंबई आई थी। किसी ने गारटी दी नहीं थी कि मुझे काम मिलेगा। मेरे साथ मेरी एक दोस्त आई थी क्योंकि मैं शहर में अकेले रहने से डरती थी। फैमिली बहुत ओवरप्रोटेक्टिव थी। उस वक्त तो दिल्ली लड़कियों के लिए बहुत अनसुख लगती थी। मेरी दिल्ली में ही अकेले रहने की हिम्मत नहीं थी। हमें हमेशा डराया जाता है कि इंडस्ट्री में सब बुरे लोग होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी फिल्में, अच्छे बैनर और अच्छे लोग भी होते हैं। मेरी कपूर परिवार से कोई लेना-देना नहीं।

कुब्रा सैत को 'राइज़ एंड फॉल' में उपमा ने रुलाया

अपनी दमदार एक्टिंग और अनूठे चुनावों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री कुब्रा सैत अब एक नए सफर पर निकल पड़ी हैं। उन्होंने टीवी के रियलिटी शो राइज़ एंड फॉल में भाग लिया है, जिसे आशीत ग़ोवर होस्ट कर रहे हैं। इस शो में प्रतियोगियों को ऐसी चरम परिस्थितियों में डाला जाता है जो वास्तविक दुनिया में धन और सत्ता की अस्मानताओं को दर्शाती हैं और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में ढलने पर मजबूर करती हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिलहाल राइज़ एंड फॉल में नजर आ रही कुब्रा ने इंस्टाग्राम पर एक रील साझा की है, जिसमें उन्होंने अपने पहले के जीवन में विदेशी व्यंजनों का आनंद लेने और वर्तमान में साधारण व सीमित भोजन पर निर्भर रहने के बीच का अंतर दिखाया। इनमें से एक डिश, उपमा, उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन अनुभव बन गया।



दुष्कर्म मामले में फंसे एक्टर आशीष कपूर को राहत

टीवी अभिनेता आशीष कपूर को पिछले हफ्ते दुष्कर्म मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक्टर को बेल पर रिहा कर दिया है। 'सरस्वतीचंद्र' फेम टीवी अभिनेता आशीष कपूर को पिछले महीने लगे दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट ने बीते 6 सितंबर को अभिनेता को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब 10 सितंबर के दिन अभिनेता को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बेल पर रिहा कर दिया। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जानिए पूरी खबर।

उनका इतिहास साफ-सुथरा है बेल मंजूर करते हुए एडिशनल सेशन जज भूपिंदर सिंह ने कहा, 'गवाहों, दस्तावेजों/सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत के संज्ञान में लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है। वे दिल्ली का स्थायी निवासी हैं और उनका इतिहास साफ-सुथरा है। इसे देखते हुए बेल देने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे स्वीकार किया जाता है।' कोर्ट ने आगे कहा, आरोपी को पुलिस रिमांड में लिए जाने के बावजूद, मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। कानून के मुताबिक, कोई तलाशी नहीं ली गई। रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया।

इन शर्तों पर किया गया रिहा आशीष कपूर को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कथित तौर पर उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अभिनेता को एक लाख रुपये के बेल बांड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। उन्हें अपना मोबाइल फोन हमेशा एक्टिव रखना होगा और लोकेशन सर्विस चालू रखनी होगी।

क्या है पूरा मामला? दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में 11 अगस्त को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली की एक हाउस पार्टी के दौरान आशीष कपूर ने वॉशरूम में उसके साथ जबरदस्ती की। शुरू में दर्ज एफआईआर में आशीष कपूर, उनके एक दोस्त, दोस्त की पत्नी और दो अज्ञात पुरुषों के नाम भी शामिल थे। महिला ने दावा किया था कि इन सभी ने मिलकर उनके साथ दुष्कर्म किया।

हाईकोर्ट का फैसला:

बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे, अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व प्रतीकों का उपयोग

बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता अभिषेक बच्चन ने पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभिषेक बच्चन की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है।

अभिनेता अभिषेक बच्चन की आवाज, नाम, तस्वीरें एवं वीडियो आदि का अवैध इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता के व्यक्तित्व प्रतीकों के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई है। बता दें कि हाल ही में अभिषेक बच्चन ने अपने पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उनके नाम या तस्वीरों के अवैध रूप से व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करने से रोक दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि बच्चन के व्यक्तित्व प्रतीकों, जिनमें उनका नाम, तस्वीरें और हस्ताक्षर शामिल हैं, का दुरुपयोग प्रतियोगिता वेबसाइटों और प्लेटफॉर्मों द्वारा उनकी इजाजत के बिना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके किया जा रहा है।

अभिनेता की साख और प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है असर

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 10 सितंबर को पारित आदेश में कहा, ये विशेषताएं बादी के पेशेवर कार्य और करियर के दौरान उनके संबंधों से जुड़ी हैं। इनके अनधिकृत उपयोग से



अभिनेता की साख और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को

फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।

ऐश्वर्या राय ने भी किया था हाईकोर्ट का रुख

अदालत ने यह अंतरिम आदेश अभिषेक बच्चन की याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जेनरेटिव अनुचित और आपत्तिजनक कंटेंट का अवैध रूप से उपयोग करने से रोकने की मांग की थी। अभिषेक बच्चन के अलावा उनकी पत्नी व अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने भी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

भारत को 2047 तक शीर्ष पांच खेल देशों में लाने के लिए योजना तैयार: मंत्री मांडविया

नई दिल्ली, एजेंसी। मांडविया ने कहा, भारत की आजादी के सौ साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने और शीर्ष पांच खेल देशों में शामिल करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। देश में खेल संस्कृति के विकास की प्रक्रिया को सिलसिलेवार और सतत बनाने पर जोर देते हुए खेलमंत्री मनसूख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के साथ शीर्ष पांच खेल महाशक्तियों में शामिल करने के लिए 10 वर्षीय और 25 वर्षीय योजना बनाई गई है जिस पर जल्दी ही अमल होगा। मांडविया ने कहा, भारत की आजादी के सौ साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने और शीर्ष पांच खेल देशों में शामिल करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

जी ने दिया है। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है जो जल्दी ही देश के सामने आएगी। इसे लागू करने के लिए नीतिगत बदलाव करने होंगे और हम इस पर जल्दी ही अमल करेंगे। स्पॉट्सस्टार प्लेकॉम बिजनेस आफ स्पॉट्स समिट 2025 में खेलमंत्री ने कहा, हमें ऐसी कार्य संस्कृति तैयार करनी होगी जिसमें प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम व्यवस्थित तरीके से हो।

इसके साथ ही दुनिया भर के देश भारत में लीग खेलने आएंगे। हमें खेल कोटे से नौकरी कर रहे अपने पूर्व खिलाड़ियों के कौशल का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। खेलमंत्री ने कहा कि देश में खेलों का इकोसिस्टम तैयार करने और खेलों को जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने



कहा, इसके लिए मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले चरण में फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी मुहिम शुरू की गई। खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं, अनुभव और आधुनिक कोचिंग देने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) शुरू हुई। इसके बाद बिजन दस्तावेज की जरूरत पड़ी तो हम खेल नीति लेकर आए। उन्होंने कहा कि खेलों में अच्छे प्रशासन के लिए सरकार खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर खेल प्रशासन विधेयक लेकर आई जिससे खेल महासंघ अदालती विवादों में मसरूफ रहने की बजाय खिलाड़ियों पर फोकस रख सके। उन्होंने कहा, पहले खेल महासंघों के 350 से ज्यादा विवाद अदालतों में थे। इस बिल में उनके निपटान की त्वरित व्यवस्था का प्रावधान भी है।

खिलाड़ियों के हितों की रक्षा

खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और महिलाओं का खेल महासंघों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। मांडविया ने कहा कि भारत में दूर दराज के इलाकों की प्रतिभाओं को मौके देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमने दुनिया भर में कैसे काम हो रहा है, यह देखा लेकिन अपना मॉडल बनाया। भारत की भौगोलिक विविधता का फायदा उठाते हुए खेलों का विकास सुनिश्चित करना है। आने वाले समय में हम खेल सेक्टर में आने वाले बदलावों को महसूस कर सकते हैं।

भारत-पाकिस्तान मैच को सियासत से दूर रखें, वे हमें नहीं हरा सकते: योगराज सिंह



चंडीगढ़, एजेंसी। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी। पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने कहा है कि भारत-पाकिस्तान मैच को सियासत से दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम हमें नहीं हरा सकती है। बात करते हुए योगराज सिंह ने कहा, भारत-पाकिस्तान मैच को मैच की तरह ही लिया जाना चाहिए। इसे लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को सियासत में नहीं खींचना चाहिए। इससे ज्यादा मैच पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में युवराज सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। इसका क्या फायदा हुआ। हम खेलते तो जीत कर आते। उस समय नहीं खेले तो फिर अब क्यों खेल रहे हैं। जब भी मौका मिले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए। आज की तारीख में पाकिस्तान टीम ऐसी नहीं है कि भारत को हरा सके। उन्होंने कहा, भारतीय टीम बहुत अच्छी और मजबूत है। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई भी टीम हमें हरा सकती है। हमारी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हमलोग देश के गौरव के लिए खेल रहे हैं। भारत की मौजूदा टीम में जो खिलाड़ी हैं, या आने वाले समय के जो खिलाड़ी हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे। इसमें आईपीएल का बहुत बड़ा योगदान है। जबतक आईपीएल है, भारतीय क्रिकेट को कोई पछाड़ नहीं सकता। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकीयों का हाथ था। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके स्थित आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे। सैन्य संघर्ष के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध न रखने की बात कही थी। माना जा रहा था कि एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच स्थगित हो सकता है। लेकिन, टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत सरकार ने एशिया कप को वैश्विक टूर्नामेंट बताते हुए भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी थी।

ब्राज़ॉसपोर में शामिल हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर आंद्रे ओनाना



मैनचेस्टर, एजेंसी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर आंद्रे ओनाना 2025/26 सीजन के लिए तुर्की के फुटबॉल क्लब ब्राज़ॉसपोर में लोन पर शामिल हो गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्लियरिंग और रजिस्ट्रेशन पर निर्भर है। यह डील शुक्रवार को तुर्की की ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले पूरी कर ली गई। ब्राज़ॉसपोर ने प्रेस रिलीज में कहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ समझौता हो गया, जिसके तहत पेशेवर फुटबॉलर आंद्रे ओनाना का 2025-26 सीजन के लिए प्री टेंपरेरी ट्रांसफर हमारे क्लब में किया गया है। कैमरून के 29 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने जुलाई 2023 में इटली के दिगज क्लब इंटर से जुड़ने के बाद रेड्स की ओर से 102 मैच खेले हैं। ओनाना ने मैनचेस्टर में अपने पहले सीजन के दौरान सिर्फ एक मैच को छोड़कर शेष सभी मुकामलों में हिस्सा लिया। उन्होंने वेबली में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ फाइनल में शानदार टीम प्रदर्शन के दम पर एफए कप जीतकर सीजन का अंत किया।

2024/25 सीजन में भी वह पहली पसंद के गोलकीपर बने रहे। ओनाना प्रीमियर लीग के सेव ऑफ द मंथ अवार्ड को तीन बार जीतने वाले पहले गोलकीपर बने।



अफरीदी ने भारत-पाकिस्तान मैच से पहले उगला जहर बेचारे जबसे पैदा हुए हैं साबित कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं

नई दिल्ली, एजेंसी। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मैच होना है। भारत में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर इस मुकामले को बहिष्कार करने की मांग हो रही है। हालांकि, भारत सरकार से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इस मुकामले को खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जहर उगला है। अफरीदी का बयान हैरानी भरा नहीं है। वह पहले भी भारत और भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं।

पाकिस्तानी मीडिया समा टीवी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें शाहिद अफरीदी अंगरूल बात करते हुए यह कहते हैं कि भारत में खिलाड़ियों को

शाहिद अफरीदी ने क्या कहा?

अफरीदी ने कहा, वहां पे बहुत ज्यादा है। घरों तक पहुंच जाते हैं। घर जलाने की धमकियां देते हैं उन खिलाड़ियों को। कुछ ऐसे हैं जो वहां साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेचारे जबसे पैदा हुए हैं साबित कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं।

घर जलाने की धमकी मिलती है। कुछ खिलाड़ी जन्म से खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगे हैं। अफरीदी का वीडियो नीचे देख सकते हैं।

इंडिया-पाकिस्तान एशिया कप 2025:

पाकिस्तान के 5 स्पिनर्स भारत के लिए खतरा कोच माइक हेसन की वॉर्निंग..कुलदीप की स्पिन पर कही ये बात

क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान का मुकामला हमेशा से सबसे बड़ी टक्कर माना जाता है। दोनों देशों के बीच 14 सितंबर को एशिया कप में यह बहुप्रतीक्षित मुकामला होना है। ऐसे में दोनों देशों के स्पिनर्स में कौन बेहतर है, भारत से टक्कर लेने को पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है? इस पर पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइंड गेम खेला।

दरअसल, हेसन ओमान संग शुक्रवार (12 सितंबर) को होने वाले मुकामले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने इस दौरान भारत संग मुकामले पर भी बात की। हेसन ने कहा- हम जानते हैं कि भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके चलते उन्हें पूरा आत्मविश्वास है और यह स्वाभाविक भी है। हम टीम के रूप में हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। हम आगे को लेकर चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनौती की गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं। हम इस मुकामले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

दलीप ट्रॉफी फाइनल: सेंट्रल जोन का स्कोर 200 रन पार-कप्तान रजत पाटीदार शतक लगाकर आउट, साउथ जोन 149 रन पर ऑलआउट

नई दिल्ली, एजेंसी। दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकामला सेंट्रल जोन और साउथ जोन के बीच बेंगलुरु के सेंट्रल ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड पर खेला जा रहा है।

आज यानी शुक्रवार को मुकामले का दूसरा दिन है। सेंट्रल जोन ने आज अपनी पहली पारी को 50/0 के स्कोर से आगे बढ़ाया। खबर लिखे जाने तक टीम ने 5



कौन हैं पाकिस्तानी टीम में 5 स्पिनर्स?

हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा- हमारी ताकत यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं। मोहम्मद नवाज इस समय दुनिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। इसके अलावा हमारे पास अब्दुल अहमद और सुफियान मुकीम भी हैं, जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सैम अयूब अब दुनिया के टॉप टेन ऑलराउंडर्स में शामिल हैं, जो उनके गेंदबाजी प्रदर्शन में सुधार का नतीजा है। सलमान अली आगा ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन वह पाकिस्तान के टेस्ट टीम के प्रमुख स्पिनर हैं।

इस दौरान पाकिस्तानी कोच हेसन ने अपनी गेंदबाजी लाइनअप पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने स्पिन

हिंसक प्रदर्शनों के कारण बदला वेन्यू

नेपाल से छीन लिया गया टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका

नई दिल्ली, एजेंसी। पहली बार आयोजित होने जा रहे महिला व्लाईड टी20 वर्ल्ड कप 2025 से पहले बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जिसे टूर्नामेंट का न्यूट्रल वेन्यू चुना गया था, अब हटा दिया गया है। इसकी वजह बनी नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और हालिया हिंसक प्रदर्शन। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 11 से 25 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा, जिसमें सात देशों की टीमों हिस्सा लेंगी - ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका। इस टूर्नामेंट में कुल 21 लीग मैच, दो सेमीफाइनल और फाइनल मुकामलों खेले जाएंगे।

अब मुकालत बिगड़ने के कारण भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ ने घोषणा की कि नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के चलते वहां



तयों हटाया गया नेपाल का वेन्यू?

पहले बनाई गई योजना के तहत यह टूर्नामेंट नई दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित होना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव को देखते हुए, पाकिस्तान के मैचों के लिए काठमांडू को न्यूट्रल वेन्यू बनाया गया था ताकि पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट में भाग ले सके।

आईएसएएसएफ वर्ल्ड कप: 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन में मेहुली-मानिनी का खराब प्रदर्शन, पदकों का खाता अब तक नहीं खुला

निंगबो (चीन), एजेंसी। भारत अब तक पदक तालिका में अपना खाता नहीं खोल पाया है। चीन दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष और मानिनी कौशी ने आईएसएएसएफ विश्व कप में शुक्रवार को यहां महिलाओं की 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन में निराशाजनक प्रदर्शन किया। भारत अब तक पदक तालिका में अपना खाता नहीं खोल पाया



है। चीन दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य

पदक के साथ शीर्ष पर है। नॉर्वे दो स्वर्ण पदक के साथ दूसरे जबकि दक्षिण कोरिया एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। मेहुली ने क्वालीफिकेशन राउंड में 583 अंक बनाकर 23वां स्थान हासिल किया, जबकि मानिनी 66 निशानेबाजों के बीच 580 अंक के साथ 45वें स्थान पर रहीं। इस स्पर्धा में भाग ले रही तीसरी भारतीय निशानेबाज सुरभि भारद्वाज 578 अंक के साथ 52वें स्थान पर रहीं।

पंजाब में फुटबॉल क्रांति: पंजाब फुटबॉल क्लब ने खोले 12 नए केंद्र, रवा सबसे बड़ा ग्रासरूट्स नेटवर्क

मोहाली, एजेंसी। पंजाब, जो कभी हॉकी और कबड्डी के लिए जाना जाता था, अब फुटबॉल की नई धड़कन बन गया है। राउंडलास स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सा पंजाब फुटबॉल क्लब ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में 12 नए डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए हैं। इस विस्तार के साथ, क्लब के पास अब कुल 26 केंद्र हो गए हैं, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल ग्रासरूट्स नेटवर्क बन गया है। यह पहल टैलेंट हर जगह है, अक्सर नहीं की विचारधारा पर आधारित है और इसका उद्देश्य पंजाब में फुटबॉल को एक संस्कृति बनाना है। इन नए केंद्रों को जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, मुक्तसर साहिब, पठानकोट, बरनाला और रूपनगर जैसे जिलों में शुरू किया गया है। हर सेंटर में अंडर-8 से लेकर अंडर-19 आयु वर्ग के सैकड़ों युवा खिलाड़ियों को प्रोफेशनल कोचिंग, न्यूट्रिशन गाइडेंस और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का स्पष्ट रास्ता मिलेगा।



बाबू अमर सिंह स्पोर्ट्स एंड यूथ क्लब, साहौली (लुधियाना) और बजवाड़ा (होशियारपुर) जैसे केंद्रों में लड़कियों को भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जो खेल में समान अवसर देने की पंजाब एफसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब एफसी का यह मॉडल अब रंग ला रहा है। कुछ ही सालों में, कई अकादमी ग्रेजुएट्स भारत की अंडर-16, अंडर-17, अंडर-19 और सीनियर टीमों का हिस्सा बन चुके हैं। यह स्ट्रक्चर्ड पाथवे यह सुनिश्चित करता है कि आज अंडर-8 में ट्रेनिंग शुरू करने वाला बच्चा सीधे इंडियन सुपर लीग (आईएसएएल) तक का सफर तय कर सके।

विकेट के नुकसान पर 276 रन बना लिए हैं। कप्तान रजत पाटीदार शतक (101 रन) लगाकर आउट हुए। ओपनर अक्षय वाडकर 22, दानिशा मालेवार 53 और शुभम शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले, गुरुवार को साउथ जोन पहली पारी में 149 रन पर ऑलआउट हो गई। सेंट्रल जोन ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। सारांश जैन को 5 विकेट साउथ जोन

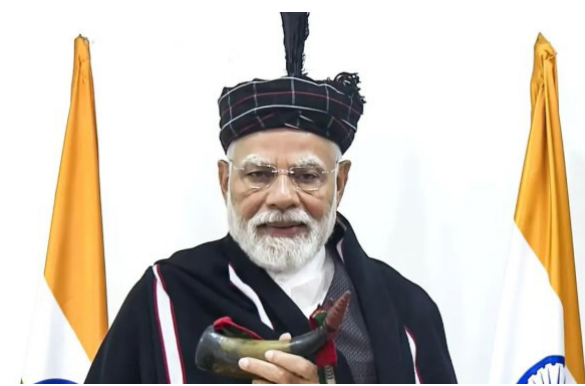
पहली पारी में 149 रन पर ही सिमट गई। टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। टीम के लिए तन्मय अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। उनके अलावा सलमान निजार 24, अंकित शर्मा 20, रिंकी भूई 15 और एमडी निधेश 12 रन बनाए। सेंट्रल जोन की ओर से सारांश जैन ने 5 और कुमार कार्तिकेय ने 4 विकेट झटकें।

मणिपुर हिंसा के दो साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा -चुराचांदपुर में शांति का संदेश, इंफाल में रोड शो

नई दिल्ली/इंफाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद यह उनका पहला आधिकारिक दौरा है। इस लंबे अंतराल के बाद पीएम की मौजूदगी ने मणिपुर की सियासत और समाज में नई हलचल पैदा कर दी है। दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले चुराचांदपुर में रोड शो और जनसभा की, जहाँ 2023 में हिंसा की सबसे भयावह घटनाएँ हुई थीं। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा— “मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है।”

हिंसा की पृष्ठभूमि
मई 2023 में मणिपुर जातीय हिंसा ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। मतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव ने सैकड़ों लोगों की जान ली और हजारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इंफाल और चुराचांदपुर दोनों ही क्षेत्र इस हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित रहे। तब से अब तक दोनों समुदायों के बीच गहरी खाई बनी हुई है। कुकी बहुल चुराचांदपुर और मतेई बहुल इंफाल के बीच आना-जाना लगभग ठप है। इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दो साल तक विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि पीएम ने मणिपुर का रुख नहीं किया, जबकि राज्य जलता रहा।

विकास की सीमाएँ
प्रधानमंत्री मोदी ने चुराचांदपुर में ₹7,300 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल से जुड़ी योजनाएँ प्रमुख हैं। पीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और शांति की बुनियाद मजबूत होगी। वे करीब दो घंटे चुराचांदपुर में रहे और इस दौरान एक रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने हिंसा से प्रभावित महिलाओं और



बच्चियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएँ सुनीं और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके पुनर्वास और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।

इंफाल में कार्यक्रम
चुराचांदपुर के बाद प्रधानमंत्री इंफाल पहुंचे। इंफाल मतेई समुदाय का गढ़ है और यहाँ हिंसा के बाद से कुकी समुदाय का आना-जाना लगभग बंद है। पीएम ने इंफाल में भी रोड शो किया और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर की एकता और भाईचारे की बहाली ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

विपक्ष का हमला
प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहे— “मणिपुर में आपका तीन घंटे का पड़व करुणा नहीं है। यह एक दिखावा और घायल लोगों का घोर अपमान है।” खड़गे ने आरोप लगाया कि दो साल तक राज्य हिंसा की आग में जलता रहा और प्रधानमंत्री मुकदमों से बच रहे। उनका यह दौरा केवल चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया कदम है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री वास्तव में संवेदनशील होते, तो वे हिंसा भड़काने के समय ही राज्य का दौरा करते और पीड़ितों के साथ खड़े रहते।

लोगों की उम्मीदें और चुनौतियाँ
मणिपुर की आम जनता प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रही है कि वे शांति बहाली के लिए ठोस पहल करेंगे। हालांकि, जमीन पर हालात अब भी नाजुक हैं। राहत कैम्पों में रह रहे हजारों लोग अपने घरों

में लौटने की स्थिति में नहीं हैं। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि एक-दूसरे के इलाकों में जाना तक मुश्किल है। प्रधानमंत्री का यह संदेश कि “भारत सरकार मणिपुर के साथ है” पीड़ितों के लिए सुकून देने वाला हो सकता है, मगर असली चुनौती राज्य में स्थायी शांति और सामंजस्य स्थापित करने की है।

राजनैतिक और सामाजिक महत्व
यह दौरा सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। मणिपुर की हिंसा ने उत्तर-पूर्व की अस्थिरता और सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब प्रधानमंत्री का सीधा हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। फिर भी, आलोचकों का कहना है कि केवल परियोजनाओं का शिलान्यास और भाषणों से हालात नहीं सुधरेंगे। जरूरत है भरोसा बहाल करने की, समुदायों को संवाद की मेज पर लाने की और उन जख्मों को भरने की, जो हिंसा ने छोड़े हैं।

आगे का रास्ता
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शांति प्रक्रिया को प्राथमिकता दें, तो मणिपुर धीरे-धीरे सामान्य हो सकता है। इसके लिए स्थानीय संगठनों, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं की भी भूमिका अहम होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने निस्संदेह एक राजनीतिक संदेश दिया है—कि मणिपुर अकेला नहीं है। परंतु अब सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि क्या यह संदेश जमीनी हकीकत में बदल पाता है या नहीं।

मोहन भागवत का बयान: भारत की मज़बूती से क्यों डर रहा है अमेरिका?

-आरएसएस प्रमुख का दृष्टिकोण: सात समंदर की दूरी पर डर क्यों?

नागपुर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित ब्रह्माकुमारी विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर अमेरिका का नाम लिए बिना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि यदि भारत मज़बूत हुआ तो उनका क्या होगा। भागवत ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि जब सात समंदर की दूरी है, तब डर कैसा? उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कदम वही लोग उठाते हैं जो हर समय चर्चा में रहना चाहते हैं। उनके बयान को सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जोनाल्ड ट्रम्प की उस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें हाल ही में भारत पर भारी टैरिफ लगाए गए। ट्रम्प ने 30 जुलाई को भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 7 अगस्त से लागू हुआ। इसके बाद 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। ट्रम्प का आरोप था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अंतरराष्ट्रीय बाजार को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। ट्रम्प का आरोप था कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुनाफे पर बेचता है और इससे रूस को अप्रत्यक्ष मदद मिलती है। ट्रम्प प्रशासन ने इसी को आधार बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। लेकिन भारत का पक्ष है कि वह केवल अपने नागरिकों के हित में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है।

मोहन भागवत का दृष्टिकोण
भागवत ने अपने बयान में यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत की मज़बूती किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए संतुलनकारी शक्ति का काम करेगी। उनका कहना था कि यदि कोई देश भारत की उन्नति से डरता है, तो यह उसकी संकीर्ण सोच का नतीजा है। दरअसल, आरएसएस प्रमुख का यह बयान केवल एक आर्थिक विवाद पर प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। आज भारत केवल आयातक देश नहीं बल्कि वैश्विक निर्यातक और निवेश का केंद्र



अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है।

रूस से तेल खरीदने का विवाद
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। इसका फायदा यह हुआ कि भारत को कम दाम पर ऊर्जा मिली और घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रहीं। लेकिन अमेरिका और यूरोप को यह नागवार गुज़रा। उनका आरोप है कि भारत सस्ता तेल लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुनाफे पर बेचता है और इससे रूस को अप्रत्यक्ष मदद मिलती है। ट्रम्प प्रशासन ने इसी को आधार बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। लेकिन भारत का पक्ष है कि वह केवल अपने नागरिकों के हित में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है।

मोहन भागवत का दृष्टिकोण
भागवत ने अपने बयान में यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत की मज़बूती किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए संतुलनकारी शक्ति का काम करेगी। उनका कहना था कि यदि कोई देश भारत की उन्नति से डरता है, तो यह उसकी संकीर्ण सोच का नतीजा है। दरअसल, आरएसएस प्रमुख का यह बयान केवल एक आर्थिक विवाद पर प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। आज भारत केवल आयातक देश नहीं बल्कि वैश्विक निर्यातक और निवेश का केंद्र

बन रहा है। ऐसे में बड़ी ताकतों का असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक है।

भारत-अमेरिका संबंधों की कसौटी
भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं। एक ओर दोनों लोकतंत्र, रक्षा और तकनीकी सहयोग में साझेदार हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापार और विदेश नीति के मामलों में टकराव भी होता है। टैरिफ का मुद्दा यही दर्शाता है कि जब भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा, तब अमेरिका जैसे देश दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। भागवत का बयान यह संकेत देता है कि भारत अब इस दबाव से घबराने वाला नहीं है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में यह साबित किया है कि वह किसी एक ब्लाॅक का हिस्सा बनने के बजाय बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर है। मोहन भागवत का बयान भारत के बदलते आत्मविश्वास का आईना है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ भले ही अल्पकालिक चुनौतियाँ खड़ी करें, लेकिन भारत की मज़बूत अर्थव्यवस्था, विविध ऊर्जा स्रोत और स्वतंत्र विदेश नीति उसे लंबे समय में ओर अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। भारत के लिए यह समय संयम और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने का है। टैरिफ जैसे कदम भारत को रोकने के बजाय और अधिक मज़बूत बनाएंगे। भागवत का सवाल—“जब सात समंदर की दूरी है, तो डर कैसा?”—वास्तव में भारत की उसी नई सोच को प्रतिबिंबित करता है जिसमें आत्मविश्वास और संतुलित कूटनीति दोनों शामिल हैं।

सुशीला कार्की के नेपाल का PM बनने की इनसाइड स्टोरी

-GenZ आंदोलन की शुरुआत: सोशल मीडिया बैन से भड़की आग

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल की राजनीति ने 5 दिनों में ऐसा नज़ारा देखा, जिसने पूरे इतिहास को हिला दिया। 8 सितंबर से शुरू हुआ GenZ आंदोलन पहले तो करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं की आवाज़ था, लेकिन यह आवाज़ जल्द ही हिंसा और आगजनी में तब्दील हो गई। संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर, यहां तक कि काठमांडू का सिंह दरबार – सब जगह लोगों का गुस्सा फूटा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। संसद भंग हुई और नई व्यवस्था के लिए रास्ता खोला गया। इस उथल-पुथल के बीच एक नाम उभरकर सामने आया – पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, जिन्हें 12 सितंबर को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई।



और युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। जब हालात बेकाबू हुए, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और वे देश छोड़कर चले गए। इससे सत्ता का शून्य पैदा हुआ।

सुशीला कार्की का नाम क्यों आया सामने
10 सितंबर को अचानक सुशीला कार्की का नाम सामने आया। 73 वर्षीय कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और उनकी छवि ईमानदार और बेबाक न्यायाधीश की रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े-बड़े नेताओं और सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ भी फैसले दिए थे। GenZ नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे खुद सत्ता संभालें या किसी ऐसे निष्पक्ष चेहरे को आगे लाएं, जिस पर जनता भरोसा करे। चूंकि आंदोलन में हिंसा और आगजनी की वजह से GenZ नेताओं पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए उन्होंने सीधे सत्ता में आने से इंकार किया। ऐसे में कार्की सबसे उपयुक्त नाम साबित हुईं।

वालें शाह की भूमिका
काठमांडू के मेयर वालें शाह पहले दिन से ही आंदोलनकारियों के साथ खड़े थे। उन्होंने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार विरोधी मांगों का खुलकर समर्थन किया। जब सुशीला कार्की का नाम आया, तो वालें शाह ने बिना शर्त उनका

समर्थन कर दिया। हालांकि शुरू में GenZ नेताओं में सहमति नहीं बनी। कुछ मानते थे कि यह आंदोलन युवाओं का है, इसलिए नेतृत्व भी युवाओं के हाथ में होना चाहिए। लेकिन बालें शाह ने समझाया कि देश को इस समय स्थिरता चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक भरोसेमंद चेहरा होना जरूरी है। उन्होंने कार्की की ईमानदार छवि का पहला दिया और कहा कि इससे आंदोलन की वैधता भी बनी रहेगी।

GenZ की शर्तें
GenZ नेताओं ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने पर कुछ शर्तें रखीं, जिनमें सबसे अहम थीं: अंतरिम सरकार का कार्यकाल सीमित हो – यह सिर्फ नई व्यवस्था और संविधान सुधार तक सीमित रहे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस – सभी पुराने मामलों की जांच और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए। युवाओं की भागीदारी – सरकार के फैसलों में युवाओं की आवाज़ शामिल हो, भले वे सत्ता का हिस्सा – किसी भी हाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी न लगे। नए चुनाव की तैयारी – 1 साल के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। सुशीला कार्की ने इन शर्तों को स्वीकार किया और यही वजह बनी कि GenZ नेता उनके नाम पर एकमत हो गए।

रूस के कामचटका में 7.4 तीव्रता का भूकंप: सुनामी अलर्ट जारी

-भूकंप के बाद 300 किमी दायरे में खतरनाक लहरों की चेतावनी

मोस्को (एजेंसी)। शनिवार को रूस के कामचटका प्रायद्वीप में एक बार फिर धरती कांप उठी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार यह भूकंप 7.4 तीव्रता का था, जो समुद्र तल से करीब 39.5 किलोमीटर गहराई में आया। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके बाद पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने समुद्र तटीय इलाकों में खतरनाक लहरों के उठने की आशंका जताई और सुनामी अलर्ट जारी कर दिया।



भूकंप की जानकारी और ताज़ा हालात
प्रारंभिक रिपोर्ट में USGS ने इस भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 7.4 किया गया। झटकों का केंद्र कामचटका प्रायद्वीप के तटीय इलाके के पास था। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और लोगों को ऊंचे इलाकों की ओर जाने की सलाह दी। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है।

सुनामी की आशंका क्यों?
भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर होने की वजह से सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में रूस के समुद्री तटों पर बड़ी लहरें उठ सकती हैं। ये लहरें जहाज़ों, तटीय इलाकों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।

लगातार बढ़ रही भूकंपीय गतिविधि
पिछले तीन महीनों में यह तीसरी बार है जब कामचटका में 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। 30 जुलाई को यहां 8.8 तीव्रता का भूकंप आया

था, जिसे दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप माना गया। इससे पहले भी जून महीने में 7 से अधिक तीव्रता का झटका महसूस किया गया था। इस लगातार गतिविधि ने वैज्ञानिकों और भूकंप विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। कामचटका: भूगोल और ज्वालामुखीय गतिविधि कामचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर-पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह इलाका “रिंग ऑफ फायर” का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक बड़ा भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र है। यहां 300 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से कई सक्रिय हैं। समुद्र तल के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों टकराहट और खिसकने की वजह से चिंता बढ़ती है और धरती की भूकंप आते रहते हैं।

भूकंप का वैज्ञानिक कारण
भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना है। कामचटका के पास प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट मिलती हैं। जब ये प्लेटें दबाव झेलने के बाद अचानक खिसकती हैं, तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और धरती कांप उठती है। समुद्र में आने वाले ऐसे भूकंप से समुद्र की गहराई में हलचल होती है, जिससे सुनामी लहरें पैदा होती हैं। कामचटका का भूगोल और समुद्र से नज़दीकी होने के कारण यहां हर भूकंप सुनामी की आशंका लिए होता है।

स्थानीय प्रशासन की तैयारी
रूसी आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार हालात पर नज़र रखे हुए हैं। तटीय इलाकों में रहने वालों को अलर्ट संदेश भेजे गए हैं। राहत दलों को तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपत स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और कई जहाज़ों को वापस बुलाया गया है।

वैश्विक स्तर पर चिंता
कामचटका का इलाका भले ही कम आबादी वाला है, लेकिन यहां के भूकंप और सुनामी का असर दूर-दराज़ तक महसूस किया जा सकता है। 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी की तरह यह क्षेत्र भी कई बार वैश्विक स्तर पर बड़ी आपदा का कारण बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बड़े झटके आने का मतलब है कि इस क्षेत्र में दबाव बहुत अधिक है, और भविष्य में इससे भी बड़ा भूकंप आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। रूस का कामचटका प्रायद्वीप प्राकृतिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका है। यहां बार-बार आने वाले भूकंप और सुनामी की चेतावनियां इस बात की याद दिलाती हैं कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान की तकनीक भी सीमित है।

मंदसौर में हॉट एयर बैलून में आग, सीएम मोहन यादव बाल-बाल बचे कलेक्टर बोलीं- यह हादसा नहीं, बैलून का कपड़ा पूरी तरह फायर प्रूफ

मंदसौर । मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट क्षेत्र में शनिवार सुबह एक रॉयल गतिविधि के दौरान बड़ा हादसा टल गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हॉट एयर बैलून की सवारी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अचानक मौसम और तकनीकी परिस्थितियों ने पल भर के लिए सबको चिंता में डाल दिया। तेज हवा और बैलून के निचले हिस्से में लगी आग ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, हालांकि सुरक्षा टीम और ग्राउंड स्टाफ की तत्परता से स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया।



हॉट एयर बैलून ने क्यों नहीं भरी उड़ान?
शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट पहुंचे। यहां पर्यटन विभाग और आयोजकों ने उनके लिए हॉट एयर बैलून की सवारी का कार्यक्रम रखा था। लेकिन उस समय हवा की रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बैलून उड़ान भरने के लिए सामान्यतः 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा अनुकूल मानी जाती है। तेज हवा के कारण बैलून असंतुलित हो सकता था। इसलिए उड़ान की अनुमति नहीं दी गई और बैलून जमीन पर ही नियंत्रित रखा गया। अचानक आग और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता

इसी बीच बैलून के निचले हिस्से, जहां से गंधी हवा छोड़ी जाती है, वहां अचानक आग लग गई। उपस्थित कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर और अन्य संसाधनों की मदद से तुरंत आग पर काबू पाया। बैलून के पास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत टूटों को संभाल लिया, जिसमें मुख्यमंत्री सवार थे। आग थोड़ी भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

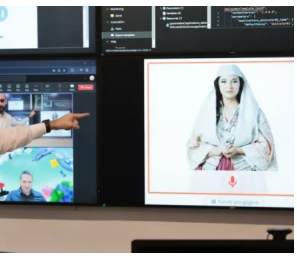
पायलट और कलेक्टर के बयान हॉट एयर बैलून के पायलट ने घटना के बाद स्पष्ट किया कि बैलून में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा फायर प्रूफ होता है। इसलिए आग फैलने या किसी गंभीर नुकसान की संभावना नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य तकनीकी स्थिति थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया।

मंदसौर कलेक्टर डॉ. सोरभ कुमार सुमन ने भी कहा कि इसे हादसा कहना ठीक नहीं होगा। तेज हवा और थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी के चलते आग जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन सबकुछ नियंत्रित था। मुख्यमंत्री और सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और गांधीसागर फेस्टिवल दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार शाम को गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट पहुंचे थे। यहां उन्होंने गांधीसागर फेस्टिवल के चौथे संस्करण की औपचारिक शुरुआत की। इस फेस्टिवल का उद्देश्य पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद हिंगलाज रिसोर्ट में रात बिताई। इस दौरान उन्होंने पर्यटन की संभावनाओं पर अधिकारियों और आयोजकों से चर्चा भी की। चंबल डैम और बैक वाटर का अनुभव शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ने चंबल डैम के बैक वाटर क्षेत्र का भ्रमण किया। वे क्रूज पर सवार होकर बैक वाटर की सुंदरता को निहारा और बोटिंग का आनंद भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

अल्बानिया बना दुनिया का पहला देश, जहां मंत्री है AI

डिएला: भ्रष्टाचार रोकने के लिए वर्चुअल मंत्री की नियुक्ति

तिराना (एजेंसी)। अल्बानिया ने दुनिया के सामने एक ऐसा कदम रखा है, जो भविष्य की राजनीति और शासन व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। देश ने अपनी कैबिनेट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित “AI मंत्री” को शामिल किया है। यह मंत्री कोई इंसान नहीं, बल्कि पिक्सल और कोड से बनी वर्चुअल इकाई है, जिसका नाम डिएला (Diella) रखा गया है। प्रधानमंत्री एडी रामा (Edi Rama) ने चौथी बार चुनाव जीतने के बाद कुछ महीनों पहले ही इसे अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया। उनका कहना है कि इस AI मंत्री का सबसे बड़ा काम सरकारी ठेकों, सार्वजनिक फंडिंग और खरीद प्रक्रिया पर निगरानी रखना है, ताकि घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगातार जवाब दे जा सके।



भ्रष्टाचार रोकने का डिजिटल हथियार
अल्बानिया लंबे समय से भ्रष्टाचार की समस्या से जूझता रहा है। सरकारी ठेकों में घोटाले, फर्जी बिलिंग और सार्वजनिक पैसों की हेराफेरी आम बात रही है। प्रधानमंत्री रामा ने कहा कि: डिएला को खास तौर पर सरकारी सामान और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पब्लिक टेंडर्स और प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बनाए रखेगी। डेटा के आधार पर यह पैटर्न पहचानकर बता सकेगी कि किस जगह पर रिश्तखोरी या मिलीभगत की संभावना है। रामा ने दावा किया कि डिएला न तो थकती है, न ही पक्षपाती होती है। यह पूरी तरह लथामें और आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेगी, इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं

को बच निकलना मुश्किल होगा।

विपक्ष का हमला: “संविधान के खिलाफ”
हालांकि इस कदम का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि – यह एक पब्लिसिटी स्टंट है, जिससे प्रधानमंत्री दुनिया भर में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। अल्बानिया के संविधान के मुताबिक मंत्री केवल इंसान हो सकता है, न कि कोई सॉफ्टवेयर। किसी भी जिम्मेदारी या जवाबदेही की स्थिति में AI मंत्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए यह लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि असली सुधार करने के बजाय सरकार तकनीक के नाम पर दिखावा कर रही है।

जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया
अल्बानिया की जनता में भी इस फैसले को लेकर उत्सुकता और आशंका दोनों हैं। एक वर्ग का मानना है कि यह कदम देश में पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मदद करेगा। वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि AI तकनीक पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। अगर सिस्टम हैक हो गया या उसमें एल्गोरिदम में गड़बड़ी हुई तो गलत फैसले भी लिए जा सकते हैं।

दुनिया के लिए संकेत
अल्बानिया का यह प्रयोग दुनिया के लिए भी एक बड़ा संकेत है। अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल प्रशासन, डेटा एनालिसिस, हेल्थकेयर और पुलिसिंग में किया गया है।